आषाढ़ कृष्ण पक्ष -अमावस्या, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 09 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
14 जुलाई 2026 मंगलवार

आज का मौसम
32.8 अधिकतम
25.6 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

पंजाब में एक बार फिर 'सेल्फ गोल' की तैयारी तो नहीं कर रही कांग्रेस?

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे अनुकूल अवसर माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी ने सत्ता विरोधी माहौल तैयार किया है। शिरोमणि अकाली दल अभी अपने पुराने जनाधार को वापस पाने के संघर्ष में है और भाजपा भी अभी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखती। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस सबसे मजबूत दावेदार बन सकती थी। लेकिन पार्टी एक बार फिर अपने विरोधियों से कम और अपने ही फैसलों से ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है।

पंजाब कांग्रेस की नई संगठनात्मक टीम की घोषणा के बाद जिस तरह असंतोष खुलकर सामने आया है, उसने पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का खुला विरोध, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और दिल्ली में डेरा डाले असंतुष्ट नेताओं का रवैया यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही आत्मघाती राजनीति की ओर बढ़ रही है।

दरअसल यह संकट नया नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव और राजनीतिक प्रयोगों के बीच अपने सबसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय इसे कांग्रेस का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग बताया गया, लेकिन चुनाव परिणामों ने उस रणनीति को गलत साबित कर दिया। विडंबना यह है कि जिन चन्नी पर कांग्रेस ने भविष्य का दांव लगाया था, वही आज पार्टी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस बार-बार उन्हीं गलतियों को क्यों दोहराती है? महीनों तक नेताओं से राय-मशविरा करने के बाद भी यदि अंतिम फैसले असंतोष को जन्म दें, तो समस्या संगठन में नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया में खोजी जानी चाहिए। राहुल गांधी और उनके आसपास का सलाहकार समूह कई बार ऐसे राजनीतिक फैसले करता दिखाई देता है, जिनका खामियाजा अंततः पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। पहले विवाद पैदा होता है, फिर डैमेज कंट्रोल शुरू होता है, लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होता है।

उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कांग्रेस के हालिया चुनावी अनुभव यही बताते हैं कि पार्टी अपनी संगठनात्मक कमजोरियों से सबक लेने के बजाय उन्हें दोहराने की आदी होती जा रही है। पंजाब में भी वही तस्वीर उभरती दिख रही है। जहां पूरी ताकत चुनावी तैयारी पर लगनी चाहिए थी, वहां नेतृत्व आंतरिक असंतोष को संभालने में उलझा हुआ है।

ऐसा राजनीतिक आत्मविश्वास !

राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई डर नहीं लगता। राजनीतिक आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन चुनावी राजनीति केवल भाषणों से नहीं जीती जाती। भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक विस्तार के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली को नजरअंदाज करना किसी भी विपक्षी दल के लिए महंगा साबित हो सकता है। भाजपा अभी पंजाब में सत्ता से दूर हो सकती है, लेकिन यदि कांग्रेस अपने ही नेताओं को संभालने में विफल रही तो वही स्थिति भाजपा के लिए अवसर बन सकती है।

अपनी ही गलतियों से ज्यादा नुकसान

राजनीति में कई बार विपक्ष की ताकत से ज्यादा नुकसान अपनी गलतियां करती हैं। पंजाब में कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी का सुनहरा अवसर है, लेकिन यदि पार्टी नेतृत्व ने समय रहते असंतोष को नहीं संभाला तो यह हार किसी प्रतिद्वंद्वी की जीत नहीं, बल्कि कांग्रेस का एक और सेल्फ गोल कहलाएगी। भारतीय राजनीति में चुनाव केवल जनसमर्थन से नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से जीते जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि उसकी अपनी निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व शैली दिखाई दे रही है।

विकराल होती जंग... अमेरिका की ईरान पर पांच घंटे बमबारी

हमारी चिंता दरकिनार... होर्मुज में टैंकर पर फिर ईरानी अटैक, भारतीय की मौत

तेहरान / वाशिंगटन डीसी, एजेंसी

यूएई के दो जहाज़ों पर दागी क्रूज मिसाइलें, 6 भारतीयों समेत 8 घायल

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका का यह दावा झूठा साबित हो रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाज़ों के लिए खुला हुआ है। दो दिन पहले एक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया था और आज फिर यूएई के दो टैंकरों पर मिसाइल अटैक हुआ जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। अपने नागरिकों की मौत पर भारत की ओर से जताई जा रही चिंता का ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है।

ओमान के नजदीक होर्मुज स्ट्रेट में यूएई के दो तेल टैंकरों पर ईरान के हमले में आज तड़के चालक दल के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई, जबकि छह भारतीयों समेत आठ अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बड़े विस्तार के रूप में सामने आई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय टैंकर 'मोम्बासा' और 'अल बहियाह' ओमान के जलक्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी उन पर ईरान की ओर से दो क्रूज मिसाइलें दागी गईं। भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के डिप्लोमैट्स को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इनमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद होसैनी भी शामिल हैं।

यूएई के मंत्रालय ने बताया कि 'मोम्बासा' टैंकर पर सवार चालक दल के एक भारतीय सदस्य की हमले में मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई गई है। उसने बताया कि घायलों में छह भारतीय और यूक्रेन के दो नागरिक शामिल हैं। बयान के अनुसार, हमले के कारण दोनों टैंकरों में आग लग गई, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस ''खुले हमले'' की निंदा करते हुए इसे ''गंभीर उल्लंघन'' और ''अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट हनन'' बताया।

मंत्रालय ने कहा, ''यूएई इस तनावपूर्ण स्थिति पर जवाब देने तथा अपने क्षेत्र, नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है।'' उसने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए मंत्रालय उच्चतम स्तर की तैयारी और सतर्कता बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब तक 11 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है।

ईरान की नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी पर हमला

इस बीच, अमेरिका ने मंगलवार तड़के ईरान पर हमले किए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकेबंदी ''फिर से लागू'' कर रहा है। उन्होंने सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के बदले अन्य जहाजों से शुल्क लेने का भी संकेत दिया। आज का हमला बंदर अब्बास स्थित सबमरीन और नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी पर सी-ड्रोन से किया गया। अईरान की नौसैनिक क्षमता को भी निशाना बनाया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा कि होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। तनाव के बीच रूस के स्पेशल कमांड एयरक्राफ्ट के तेहरान पहुंचने की खबर है। यह विमान परमाणु या बड़े युद्ध के दौरान राष्ट्रपति और सेना के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

फीफा वर्ल्डकप का पहला सेमीफाइनल

20 साल बाद फुटबॉल वर्ल्डकप में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला आज

डलास, एजेंसी। फ्रांस और स्पेन 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच 2026 वर्ल्डकप का पहला सेमीफाइनल भारतीय समय अनुसार आज देर रात 12:30 बजे डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इससे पहले दोनों की आखिरी भिड़ंत 2006 में हुई थी, जब फ्रांस ने राउंड-16 में स्पेन को 3-1 से हराया था। ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक 38 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीत है। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे शानदार फॉर्म में हैं। वे मौजूदा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं।

रोहित-विराट की वापसी... भारत-इंग्लैंड के बीच पहला वनडे आज

बर्मिंघम। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे टीम में वापसी करेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कोई वनडे नहीं खेला है।

विस्तृत खबर पेज-7 पर

द्विशा शर्मा मौत मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई

भोपाल। भोपाल की चर्चित मॉडल और अभिनेत्री द्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आज जिला अदालत में दोपहर बाद अहम सुनवाई होने वाली है। मामले की आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे, अधिवक्ता समर्थ सिंह को न्यायिक हिरासत से एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है।

चारा घोटाले में लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रहेगी बरकरार

पटना। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने की CBI की मांग भी स्वीकार नहीं की। लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में जमानत दी गई थी।

न्यूज विंडो

पहलगाम हमले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

श्रीनगर। भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब आतंक के सबसे बड़े चेहरों में शामिल लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद पर कानूनी शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। जम्मू की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अपील पर हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही एजेंसी अब उसे 'घोषित अपराधी' घोषित कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

वियतनाम नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के शव मुंबई लाए गए

मुंबई, एजेंसी। वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास हुए नाव हादसे में मारे गए सभी 15 भारतीय टूरिस्टों के शव बीती रात मुंबई लाये गए। शवों को वियतनाम एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट देर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज को शवों को उनके संबंधित दक्षिणी राज्यों में ले जाया जाएगा और खास सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा।

आज का कार्टून

रन-वे के पास है 136 साल पुरानी मस्जिद

कोलकाता एयरपोर्ट की बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक और 'नो एंट्री' से बवाल

कोलकाता, एजेंसी। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद (बांकरा मस्जिद) में नमाज़ पढ़ने और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाने से एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद छिड़ गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, रनवे सुरक्षा और एयरपोर्ट विस्तार का हवाला देते हुए मस्जिद में सामूहिक नमाज़ और बाहरी लोगों के प्रवेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। दमदम

हवाई अड्डे पर दो रनवे हैं। मुख्य रनवे का उपयोग विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा रनवे छोटा है। मस्जिद उस रनवे से थोड़ी दूरी पर स्थित है।

हवाई अड्डे के द्वितीय रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर स्थित इस प्राचीन मस्जिद को हटाने और बाहर एक नई जगह पर स्थानांतरित करने पर चर्चा चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह मामला स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और कोई भी फैसला समुदाय की सहमति से ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से यह मस्जिद वहां मौजूद है और इसे हटाने का विवाद हाल के वर्षों में ही सामने आया है। जबकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए इस प्रतिबंध का समर्थन किया है।

30 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम

सीएम डॉ. मोहन यादव आज लॉन्च करेंगे नशे से दूरी का अभियान

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार अपनी मुहिम को और तेज़ करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजधानी के रवींद्र भवन में 'नशा से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

यह अभियान 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रखना, लोगों में जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी बढ़ाना है। अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों को नशा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले भी नशा मुक्ति को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बता चुके हैं।

मेट्रो एंकर

87 देशों के बीच हमारे स्टूडेंट्स ने रचा इतिहास, संयुक्त रूप से हासिल की वर्ल्ड नंबर 1 रैंक

भारत का डंका... फिजिक्स ओलंपियाड में पांच गोल्ड के साथ लहराया तिरंगा

नई दिल्ली, एजेंसी

दुनिया भर के 87 देशों के बीच भारत के विद्यार्थियों ने इतिहास रचा है। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम के सभी पांच स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और देश ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। देश के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने कमाल किया था।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की इस प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस कामयाबी से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत का शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हुआ है। इस बार हर भारतीय प्रतिभागी ने मेडल जीता है। प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी बांटे गए हैं।

गोल्ड मेडल जीतने वाले छात्र

कनिष्क जैन (पुणे, महाराष्ट्र)
रिद्वेश अनंत बेंडले (इंदौर, मध्य प्रदेश)
ऋषित गर्ग (द्वारका, नई दिल्ली)
श्रेष्ठ सुरैया (मुंबई, महाराष्ट्र)
स्वरित जोशी (अहमदाबाद, गुजरात)।

यह प्रतियोगिता बिल्कुल भी आसान नहीं थी। प्रतिभागियों को 5 घंटे की एक मुश्किल थ्योरी परीक्षा देनी थी, जिसमें फिजिक्स के कठिन सवाल शामिल थे। थ्योरी में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और मॉर्डन फिजिक्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में प्रयोग करना, माप लेना, डेटा का एनालिसिस, ग्राफ बनाना और परिणाम निकालना शामिल होता है। भारतीय छात्रों ने समस्याओं को हल करने की क्षमता दिखाई। कई प्रतिभागी थ्योरी परीक्षा में पूरे अंक पाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। इसके अलावा 5 घंटे के प्रैक्टिकल में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारतीय ओलंपियाड कार्यक्रम का संचालन 'होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन' करता है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' का एक राष्ट्रीय केंद्र है।कई चरणों वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभाशाली प्री-यूनिवर्सिटी छात्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद के जाती है।

करोड़ों की स्मार्ट पार्किंग बदहाल, रखरखाव के अभाव में व्यवस्था पर उठे सवाल

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी के एमपी नगर में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से विकसित की गई स्मार्ट पार्किंग की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। नियमित रखरखाव के अभाव में यह सुविधा अब अपनी उपयोगिता खोती नजर आ रही है। स्थानीय व्यापारियों, वाहन चालकों और आम नागरिकों का कहना है कि स्मार्ट पार्किंग का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था, लेकिन बदहाल हालत के कारण लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्षेत्र में कई स्थानों पर पार्किंग परिसर की साफ-सफाई, संकेतक, आधारभूत सुविधाएं और रखरखाव की कमी साफ दिखाई देती है। नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से समय-समय पर निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत नहीं कराई जा रही, जिससे पार्किंग व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एमपी नगर शहर का प्रमुख व्यापारिक और कार्यालय क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन पहुंचते हैं। ऐसे में स्मार्ट पार्किंग की दुर्दशा के कारण कई वाहन चालक सड़क किनारे वाहन खड़े करने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। हाल ही में एमपी नगर सहित प्रमुख क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगरानी और ई-चालान जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल स्मार्ट पार्किंग का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत, नियमित साफ-सफाई और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करे, ताकि करोड़ों रुपए की इस सार्वजनिक सुविधा का उद्देश्य पूरा हो सके।

निजी कॉलेज और बैंक की मिलीभगत का खुलासा, सीबीआई ने शुरू की जांच

स्कॉलरशिप के नाम पर 99 लाख की ठगी 118 छात्रों के फर्जी खातों से निकाली राशि

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी में छात्रवृत्ति राशि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। निजी कॉलेज के 118 एमबीए विद्यार्थियों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर करीब 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। पिछले महीने एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच एजेंसी आरोपितों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।

मामला यूको बैंक की हबीबगंज शाखा और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, भोपाल से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच विद्यार्थियों की जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम पर बचत खाते खोले गए। सरकारी छात्रवृत्ति की राशि इन खातों में जमा कराई गई और बाद में उसे निकाल लिया गया। सीबीआई ने यूको बैंक हबीबगंज शाखा की तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक प्रेमा वर्मा सहित कॉलेज से जुड़े विनय मल्होत्रा, आदित्य मल्होत्रा, मनोज जैन, राम सिंह वर्मा और विनेश मेश्राम को आरोपित बनाया है। जांच में फर्जी दस्तावेज, जाली हस्ताक्षर और केवाईसी नियमों की अनदेखी की बात सामने आई है। अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की भूमिका और अन्य संभावित आरोपितों की जांच कर रही है।

फाइल फोटो।

छात्रों की पहचान का हुआ दुरुपयोग

118 एमबीए विद्यार्थियों के नाम पर बिना उनकी जानकारी के बैंक खाते खोले गए। छात्रों को न तो खाते खुलने की सूचना दी गई और न ही उन्हें बैंकिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया। आरोप है कि कॉलेज से जुड़े लोगों ने छात्रों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर खाते खुलवाए और सरकारी छात्रवृत्ति की राशि उन खातों में ट्रांसफर करवा ली। इससे न केवल छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या अन्य छात्रों के नाम पर भी इसी तरह की गड़बड़ी की गई थी।

फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षरों से खुला खेल

सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि खाते खोलने के लिए फर्जी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया। आरोपितों ने खातों से अपने मोबाइल नंबर लिंक कराए, एटीएम कार्ड हासिल किए और छात्रवृत्ति की राशि निकाल ली। बैंकिंग प्रक्रिया में जरूरी सत्यापन और दस्तावेजों की जांच नहीं होने से यह पूरा खेल लंबे समय तक चलता रहा। जांच एजेंसी अब बैंक रिकॉर्ड, खाता संचालन और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि पूरे फर्जीवाड़े की परतें खोली जा सकें।

बैंक की लापरवाही भी जांच के दायरे में

मामले में यूको बैंक की हबीबगंज शाखा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने अनिवार्य केवाईसी सत्यापन और खाताधारकों की पहचान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यदि बैंकिंग नियमों का सही तरीके से पालन किया जाता तो इतने बड़े स्तर पर फर्जी खाते खुलना संभव नहीं था। यूको बैंक के जोनल हेड की शिकायत के बाद मामला सीबीआई तक पहुंचा। अब जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि यह केवल लापरवाही थी या फिर इसमें मिलीभगत भी शामिल थी।

भोपाल नगर निगम में टैक्स चोरी पर बड़ा एक्शन

क्षेत्रफल घटाकर कर रहे थे हेराफेरी 460 से ज्यादा संदिग्ध खाते रडार पर

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल नगर निगम के राजस्व विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े रिकार्ड की व्यापक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती ऑडिट में 460 से अधिक ऐसे संदिग्ध खाते सामने आए हैं, जिनमें टैक्स निर्धारण और रिकार्ड संधारण में भारी अनियमितताओं की आशंका है। हाल ही में टैक्स हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद निगम ने यह कदम उठाया है।

सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि कई रसूखदारों की संपत्तियों का वास्तविक क्षेत्रफल रिकार्ड में जानबूझकर कम दर्ज किया गया, जिससे निगम को मिलने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में लाखों रुपये का चूना लगा है। इसके अलावा कुछ मामलों में निगम के खजाने में राशि जमा हुए बिना ही टैक्स क्लियरेंस की रसीदें जारी करने का भी अंदेशा है। प्रारंभिक जांच में सबसे ज्यादा करीब 130 संदिग्ध खाते जोन-एक के वार्ड-तीन में मिले हैं। इसके अलावा जोन-2, 6, 7, 10, 13 और 17 की फाइलें भी जांच के दायरे में हैं। राजस्व विभाग अब हर खाते का ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलान कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिकार्ड में यह बदलाव किस स्तर पर और किन अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत से किए गए।

71 वर्षीय बुजुर्ग के बैग से 8 लाख के जेवर लेकर चंद मिनटों में फरार हुए तीन शातिर

भोपाल। राजधानी के बाग सेवनिया क्षेत्र में एक बुजुर्ग ऑटो में सफर के दौरान शातिर चोरों का शिकार हो गए। तीन युवक सवारी बनकर ऑटो में बैठे और मौका मिलते ही 71 वर्षीय बुजुर्ग के बैग से करीब आठ लाख रुपए के जेवरों से भरा बैग पार कर दिया। चोरी का पता चलते ही बुजुर्ग ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे अपार्टमेंट के रास्ते फरार हो गए। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ऑटो चालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पेबल वे कॉलोनी निवासी मोतीलाल पटेल, जो सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं। वह रेवांचल एक्सप्रेस से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां से उन्होंने पेबल वे कॉलोनी जाने के लिए ऑटो किया। रास्ते में बाग सेवनिया थाने के पास ऑटो चालक ने तीन युवकों को भी सवारी के रूप में बैठा लिया। इस दौरान युवकों ने उनका बैग पीछे रख दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद मोतीलाल ने बैग देखा तो उसमें रखा जेवरों का डिब्बा गायब था।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र विवाद में मंत्री प्रतिमा बागरी को मिली क्लीन चिट

110 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र सही पाया गया

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत मिल गई है। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र को वैध मानते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस फैसले से कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को बड़ा झटका माना जा रहा है।

मामला कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार की शिकायत से जुड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिमा बागरी सामान्य वर्ग से संबंधित हैं और एससी के लिए आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। छह जुलाई को मंत्रालय में हुई सुनवाई के दौरान मंत्री ने अपने पक्ष में 110 वर्ष पुराने खसरा-खतौनी सहित कई दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया कि किसी भी रिकॉर्ड में बागरी समाज को राजपूत नहीं बताया गया है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस स्वयं अतीत में एससी आरक्षित सीटों से बागरी समाज के प्रत्याशी उतारती रही है।

वहीं, शिकायतकर्ता ने 430 पृष्ठों के दस्तावेज और विभिन्न राज्यों के गजट का हवाला देते हुए अपने आरोपों का समर्थन किया। हालांकि समिति ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को सही माना और उन्हें राहत प्रदान की।

प्रोफेसर के फटे कपड़े, पूर्व सैन्य अधिकारियों से की अभद्रता, पुलिस ने दर्ज की एनसीआर

विवादित मार्ग को लेकर राजधानी की रक्षा विहार कॉलोनी में बवाल

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी की रक्षा विहार कॉलोनी में एक विवादित रास्ते को लेकर जमकर हंगामा और धक्का-मुक्की हुई। आरोप है कि निजी कॉलोनी के लिए खोले गए मार्ग का विरोध करने पर कॉलोनी के रहवासियों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। घटना में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के प्रोफेसर विनीत कुमार शर्मा के कपड़े फाड़ दिए गए, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

इंदौर बायपास रोड स्थित रक्षा विहार कॉलोनी में बड़ी संख्या में सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और उनके परिवार रहते हैं। रहवासियों का आरोप है कि पूर्व सैन्य अधिकारी राममोहन सिंह सेंगर ने कॉलोनी से सटी अपनी निजी टाउनशिप विकसित की है और उसके लिए रक्षा विहार के विवादित मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। यह मामला पहले से न्यायालय में लंबित है। रविवार को कॉलोनीवासियों ने मौके पर 'यह रास्ता विवादित है' का बोर्ड लगाया था। आरोप है कि इसके बाद राममोहन सिंह सेंगर, उनके परिजन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से विवाद करने लगे। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। घटना में प्रोफेसर विनीत शर्मा के साथ मारपीट और उनके कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया गया है। वहीं, रिटायर्ड कमांडर अरविंद शुक्ला और पूर्व विंग कमांडर मनीष मिश्रा के साथ भी अभद्रता किए जाने की शिकायत सामने आई है। परवलिया पुलिस ने शिकायत के आधार पर एनसीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह है विवादित रास्ते का मामला

रक्षा विहार कॉलोनी और उससे सटी निजी कॉलोनी के बीच बने एक मार्ग को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रक्षा विहार के रहवासियों का कहना है कि यह रास्ता न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आने तक इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि निजी कॉलोनी के विकास के लिए इस मार्ग को चौड़ा कर आवागमन के लिए खोला गया, जिससे सुरक्षा और स्वामित्व से जुड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर, संबंधित पक्ष इस रास्ते के उपयोग को वैध बता रहा है। रविवार को विवादित स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के बाद तनाव बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

रक्षाबंधन से पहले न्यू मार्केट में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

भोपाल। दोपहर मेट्रो

आगामी रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों को देखते हुए राजधानी के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र न्यू मार्केट को अस्थाई अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारी कर ली गई है। टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार (कल) से नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से बड़े स्तर पर मुहिम शुरू की जाएगी। इसके तहत बाजार के भीतर और बाहर सड़कों-फुटपाथों पर जमे अस्थाई दुकानदारों को हटाकर टीटी नगर स्टेडियम के पास खाली जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे त्योहारों पर खरीदारों को परेशानी न हो। एसडीएम अर्चना शर्मा ने कहा कि कि त्योहारों पर भीड़ और जाम से जनता को निजात दिलाने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है। इस बार हटाने के बाद दोबारा दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन बेहद कड़ाई से पेश आएंगे।

पीली लाइन भी हुई फेल, अब प्रशासन दिखाएगा सख्ती: न्यू मार्केट में सालों से कपड़े, जूते, बैग और खाद्य पदार्थों की सैकड़ों अवैध दुकानें लग रही हैं। त्योहारी सीजन में यहां पैर रखने तक की जगह नहीं बचती, जिससे व्यापारी महासंघ लंबे समय से इन्हें हटाने की मांग कर रहा है। इससे पहले दुकानों के सामने खींची गई पीली लाइन का नियम भी बेअसर साबित हुआ और नगर निगम की कार्रवाई के बाद फुटकर विक्रेता फिर लौट आते थे।

मेट्रो एंकर

समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी UCC की रिपोर्ट, मां-पिता को भी मिलेगी सूचना

एमपी में बिना रजिस्ट्रेशन लिव-इन में रहना होगा अपराध

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाने के लिए कड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा। यदि कोई जोड़ा बिना पंजीयन के साथ रहता है और इसकी जानकारी प्रशासन को मिलती है तो इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

पंजीयन होने पर इसकी सूचना संबंधित थाने और दोनों पक्षों के स्वजनों को भी दी जाएगी। वहीं, लिव-इन संबंध समाप्त करने के लिए भी रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार लिव-इन संबंध से जन्म लेने वाली संतान को सभी वैधानिक और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे। समिति ने आदिवासी, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु और मतांतरित आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की है। सरकार की मंजूरी, कैबिनेट अनुमोदन, विधानसभा से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून लागू हो सकेगा। यूसीसी लागू होने पर मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन जाएगा।

लिव-इन संबंधों के लिए यह होंगे नए नियम

प्रस्तावित यूसीसी में लिव-इन संबंधों के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तैयार की गई है। इसके तहत साथ रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने और परिवार के सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी। यदि कोई जोड़ा बिना पंजीयन के लिव-इन में रहता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। संबंध समाप्त करने की स्थिति में भी रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा संबंधों में पारदर्शिता आएगी।

उत्तराधिकार और विवाह कानून में होंगे बड़े बदलाव

यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम सभी समुदायों के लिए समान हो जाएंगे। किसी भी वर्ग को विशेष कानूनी छूट या अलग व्यवस्था नहीं मिलेगी। लिव-इन संबंधों से जन्मी संतान को संपत्ति और उत्तराधिकार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार बच्चे की संपत्ति पर माता और पिता दोनों का अधिकार रहेगा। वहीं, पति की मृत्यु की स्थिति में उसकी माता के अधिकारों को भी संरक्षित किया जाएगा। हालांकि आदिवासी और घुमंतु समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की गई है।

एमपीआरडीसी की बड़ी तैयारी : एक नेटवर्क से जुड़ेंगे एमपी के 149 टोल प्लाजा

गड़बड़ियों पर लगेगी रोक, निगरानी होगी हाइटेक; जारी हुआ टेंडर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश के 149 टोल प्लाजा अब एक ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने सभी टोल प्लाजाओं को भोपाल मुख्यालय से मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क के जरिए जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद भोपाल मुख्यालय से हर टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। किसी भी टोल प्लाजा पर नेटवर्क डाउन होने, कनेक्टिविटी बाधित होने, डेटा ट्रांसफर में गड़बड़ी या बैंडविड्थ कम मिलने की सूचना तत्काल मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। इस कार्य के लिए 3.81 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

टोल संचालन में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी

इससे टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व संग्रह की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और तकनीकी गड़बड़ियों का समय रहते समाधान किया जा सकेगा। ग्वालियर संभाग के टोल प्लाजा भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे यहां के टोल संचालन पर भी भोपाल से सीधी नजर रखी जा सकेगी।

परियोजना के तहत प्रत्येक टोल प्लाजा को समर्पित एमपीएलएस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जबकि भोपाल स्थित मुख्यालय को हाइ-स्पीड नेटवर्क हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी टोल प्लाजा एक केंद्रीकृत डिजिटल नेटवर्क के दायरे में आ जाएंगे।

ऑनलाइन निगरानी और त्वरित तकनीकी समाधान की व्यवस्था

परियोजना के तहत प्रत्येक टोल प्लाजा को जोड़ा जाएगा समर्पित एमपीएलएस नेटवर्क से

भोपाल मुख्यालय से प्रत्येक टोल प्लाजा की कनेक्टिविटी, नेटवर्क की उपलब्धता, डेटा ट्रैफिक और नेटवर्क डाउन होने जैसी तकनीकी गतिविधियों की आनलाइन निगरानी की जाएगी। यदि किसी टोल प्लाजा का नेटवर्क बाधित होता है या डेटा ट्रांसमिशन में कोई समस्या आती है तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल सेंटर को मिलेगी। इससे खराबी का जल्द पता लगाकर उसे कम समय में दूर किया जा सकेगा और टोल संचालन प्रभावित नहीं होगा। साथ ही टोल संचालन से जुड़े आंकड़ों का केंद्रीकृत रिकार्ड तैयार होगा, जिससे राजस्व प्रबंधन, परिचालन समीक्षा और भविष्य की योजना बनाने में आसानी होगी। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल नेटवर्क तैयार होने के बाद तकनीकी बाधाओं में कमी आएगी, टोल संचालन अधिक व्यवस्थित होगा और पूरे प्रदेश में एमपीआरडीसी की सड़क परियोजनाओं की निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकेगी।

किस डिवीजन के कितने टोल आएंगे दायरे में

एमपीआरडीसी ने अपने भोपाल डिवीजन के 20, ग्वालियर डिवीजन के 19, छिंदवाड़ा के आठ, धार के 20, इंदौर के नौ, जबलपुर के 10, नर्मदापुरम के तीन, रीवा के 13, सागर के 15, शहडोल के नौ और उज्जैन के 23 टोल प्लाजा को इसमें शामिल किया है।

ग्वालियर डिवीजन के चिह्नित टोल प्लाजा

ग्वालियर डिवीजन के उमरी टोल प्लाजा, देवखेड़ी, बिलौआ, लुक्की, बसवाहा, भीमपुरा, पंडोला, बरेठा, फूप, पलोथर, पगारा, फुटेरा, रतवई, चितोरा, धनेली, सौसा, मौ, मगरौनी और केरुआ टोल प्लाजा को इस प्रोजेक्ट में चिह्नित किया है।

भारत टेक्स-2026 में मध्यप्रदेश का बड़ा दांव

सीएम दिल्ली में तलाशेंगे टेक्सटाइल निवेश की नई संभावनाएं, उद्योगपतियों से करेंगे संवाद

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 17 अप्रैल तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत टेक्स-2026 में हिस्सा लेकर देश-विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश में नए निवेश, उत्पादन विस्तार और रोजगार सृजन की संभावनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। भारत टेक्स-2026 के दौरान मुख्यमंत्री प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एकल उद्योग बैठकें करेंगे। इनमें टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों, उत्पादन इकाइयों के विस्तार, निर्यात बढ़ाने और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य इन बैठकों के माध्यम से प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को नई गति देना है। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहेंगे। निवेश संवर्धन, कौशल विकास और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। साथ ही कंपनियों को जनवरी 2027 में मध्यप्रदेश में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

मप्र के टेक्सटाइल क्षेत्र को मिलेगी वैश्विक मंच पर नई पहचान

एमपी का विशेष पेवेलियन दिखाएगा औद्योगिक ताकत

भारत टेक्स-2026 में मध्यप्रदेश का विशेष पेवेलियन राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और टेक्सटाइल क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन को प्रदर्शित करेगा। निवेशकों को बताया जाएगा कि मध्यप्रदेश में कपास उत्पादन से लेकर स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग और गारमेंट निर्माण तक संपूर्ण औद्योगिक नेटवर्क उपलब्ध है। प्रदेश को देश के प्रमुख ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्यों में शामिल किया जाता है। सरकार फार्म-टू-फैशन की अवधारणा पर टेक्सटाइल इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। धार जिले में लगभग 2,158 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क भी निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण होगा।

100 से ज्यादा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ होगी रणनीतिक चर्चा

कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के लिए आयोजित विशेष राउंड टेबल बैठक में टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग से जुड़े 100 से अधिक उद्योगपति, निवेशक और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। बैठक में वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात बढ़ाने, सतत विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों के आधार पर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग के विस्तार के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार का उद्देश्य निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियां बनाकर मध्यप्रदेश को टेक्सटाइल उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश की उन खूबियों को भी रखेंगे, जिनके कारण प्रदेश टेक्सटाइल निवेश के लिए तेजी से उभर रहा है। राज्य में पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति, भूमि संबंधी रियायतों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में निवेश बढ़ने से प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत टेक्स-2026 के मंच से मध्यप्रदेश न केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेगा, बल्कि वैश्विक उद्योग जगत के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा।

दतिया उपचुनाव:भाजपा-कांग्रेस के कैंडिडेट करोड़पति

घनश्याम 20 करोड़ तो बीजेपी के आशुतोष 1.79 करोड़ के मालिक, पत्नी के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति

दतिया, दोपहर मेट्रो

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से कई गुना ज्यादा अमीर हैं। घनश्याम 20.08 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। जबकि आशुतोष तिवारी के पास 1.79 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

यह जानकारी दोनों के नामांकन फॉर्म के साथ लगाए गए शपथ-पत्र में सामने आई है। दतिया राजघराने के मुखिया घनश्याम सिंह के पास साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा की कृषि भूमि और ढाई करोड़ की गैर-कृषि भूमि के साथ-साथ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं।

दोनों की पत्नियों की संपत्ति का अंतर ठीक उलट है। घनश्याम सिंह खुद भले ही ज्यादा संपत्ति के मालिक हों, लेकिन उनकी पत्नी के पास करीब 84.17 लाख रुपए की संपत्ति है।

इसके उलट, आशुतोष की पत्नी कल्पना के पास करीब 1.76 करोड़ रुपए की मालिकियत है। जिसमें अकेले उनके पास 1.31 करोड़ रुपए की कृषि भूमि शामिल है। घनश्याम सिंह के खिलाफ तीन केस रजिस्टर्ड हैं। जबकि आशुतोष का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

दोनों की पत्नियों के पास ज्यादा सोना- सोना रखने के मामले में पत्नियां अपने-अपने पतियों से आगे हैं। घनश्याम सिंह के पास कुल 240 ग्राम सोना है। जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 580 ग्राम सोना है। वहीं, आशुतोष के पास 80 ग्राम सोना है। पत्नी कल्पना के पास 312 ग्राम सोना है। घनश्याम सिंह के पास 1.80 लाख रुपए कैश हैं, जबकि आशुतोष के पास 1 लाख 54 हजार 500 रुपए की नकदी है। आशुतोष के पास बैंकों का कुल 11.83 लाख रुपए का कर्ज है। जबकि घनश्याम सिंह पर 5.63 लाख रुपए की देनदारी है।

जिले में 32 नामांकन किए गए दाखिल

सोमवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन प्रत्याशियों के नामांकन लिए गए। अब आज नामांकन की जांच की जाएगी। जिले में कुल 32 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रत्याशियों ने दो-दो नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें भाजपा के आशुतोष ने दो, घनश्याम सिंह ने तीन और दामोदर ने दो नामांकन दाखिल किए हैं। कोई भी प्रत्याशी 16 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले सकता है।

70 हजार यूथ सर्वेयर की सरकार को चेतावनी

मांगें नहीं मानीं तो विस गेट पर धरना, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में 70 हजार से ज्यादा लोकल यूथ सर्वेयर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। लंबित मांगों को लेकर लोकल यूथ महासंघ मध्यप्रदेश ने चेतावनी दी है कि अब केवल ज्ञापन और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन की शुरुआत भोपाल से होगी और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचेगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही प्रदेशभर से हजारों लोकल यूथ सर्वेयर भोपाल पहुंचेंगे। विधानसभा गेट पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे।

जंतर-मंतर पर उतरेंगे 70 हजार सर्वेयर

महासंघ ने दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि सरकार की अनदेखी जारी रही तो 70 हजार से अधिक लोकल यूथ सर्वेयर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुटकर विशाल प्रदर्शन करेंगे। गोस्वामी ने कहा कि सर्वेयर अपनी समस्याओं और पीड़ा से सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। लगातार इंतजार के बाद युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। अब सरकार को मांगों पर निर्णय लेना होगा, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। लोकल यूथ महासंघ ने सरकार के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सर्वेयर के लिए नियम बनाकर अलग कैडर तय करना, नियमित रोजगार और सम्मानजनक निश्चित मासिक मानदेय देना शामिल है। संगठन ने नई नियुक्तियों की प्रक्रिया बंद कर मौजूदा लोकल यूथ सर्वेयर को पटवारी सहायक का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड जारी करने तथा आगामी पटवारी भर्ती में लोकल यूथ सर्वेयर के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण की मांग भी उठाई गई है।

बीमा कवर-डिजिटल क्रॉप सर्वे के नियम बदलने की मांग

महासंघ ने सर्वेयर की सुरक्षा के लिए बीमा कवर देने की मांग की है। खरीफ गिरदावरी में 100 मीटर और रबी व जायद गिरदावरी यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खसरे से 50 मीटर की दूरी का प्रावधान लागू करने की मांग भी सरकार के सामने रखी गई है। संगठन की मांग है कि लोकल यूथ सर्वेयर से जुड़ी मांगों पर आगामी विधानसभा सत्र में निर्णय लिया जाए और राज्य स्तरीय सर्वेयर महापंचायत आयोजित की जाए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने इस बार भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो भोपाल से शुरू होने वाला आंदोलन दिल्ली तक जाएगा।

प्रहलाद पटेल ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिए निर्देश

ग्रामीण सड़क निर्माण की गुणवत्ता, समयबद्ध निर्माण और तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की नीतियों के अनुरूप कार्य प्रणाली अपनाने तथा विभाग की सभी विंगों के बेहतर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-मन योजना के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने तथा माय गॉव से मजरा-टोला सड़क डिजाइनों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही विभागीय प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बैच-1 में 973 मार्ग (2,117 किलोमीटर) स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 987 बसाहटों को लाभ मिलेगा, जबकि बैच-2 में 2,032 मार्गों पर कार्य प्रस्तावित है। क्षतिग्रस्त 1,776 पुलों में से 380 पुलों के पुनर्निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में दी गई यह जानकारी

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारी वाहनों के आवागमन से प्रभावित 5,388 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 5,166 किलोमीटर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 350 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माइनिंग से प्रभावित मार्गों के उन्नयन के लिए एमपीएसईडीसी के माध्यम से सैटेलाइट इमेज विश्लेषण कराया जा रहा है, जिसमें 1,119 मार्गों को प्राथमिक रूप से चिन्हित किया गया है।

पढ़ाई के लिए 10 माह का वेतन छोड़ने तैयार विधायक डोडियार

भोपाल। राजनीति में जहां जनप्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चा होती है, वहीं सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अलग मिसाल पेश की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर करीब 10 महीने तक विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ता नहीं लेने का अनुरोध किया है। डोडियार ने बताया कि उनका चयन भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के एक वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम में हुआ है। नियमित अध्ययन और विश्वविद्यालय के उपस्थिति नियमों का पालन करने के कारण उन्होंने 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक विधायक वेतन और भत्ते का भुगतान स्थगित करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी प्रकार के दबाव में नहीं लिया गया है। भविष्य में आवश्यकता होने पर वे वेतन और भत्ते दोबारा शुरू करने के लिए अलग से आवेदन देंगे। डोडियार ने कहा कि पढ़ाई के दौरान भी वे अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हटेंगे। विधानसभा सत्र में प्राथमिकता से शामिल होंगे, क्षेत्र में जनसुनवाई करेंगे, सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे।

मेट्रो एंकर — बुवाई का काम ठप और अंकुरित पौधे झुलसे, कृषि विभाग ने घटाया लक्ष्य

कम बारिश और बढ़ते तापमान से खरीफ फसलों पर संकट का साया

ग्वालियर, दोपहर मेट्रो

अंचल में इस बार कम वर्षा से वर्तमान में खरीफ की फसल की बुवाई से लेकर बोई गई फसल पर संकट के बादल छा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी एक सप्ताह तक अंचल में तकरीबन न के बराबर वर्षा होने की बात कही है। यदि वर्षा का यह अंतराल लंबा हो जाता है तो अंचल की धान के साथ-साथ ज्वार, बाजरा सहित अन्य फसलों की बुवाई के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी की थी और इस बार कम वर्षा का अंदेशा जताते हुए कम पानी की फसलों की बुवाई करने के लिए कहा था।

यहां बता दें कि इस बार मानसून सात दिन की देरी से आया और जुलाई माह में जिस तरह से अंचल में वर्षा होती थी, उस तरह से नहीं हुई। ऐसे में खरीफ की फसल की बुवाई का काम पहले से ही धीमा था, लेकिन पिछले दो दिन से तकरीबन वर्षा गायब हो गई, बल्कि मौसम विभाग ने भी तकरीबन एक सप्ताह तक वर्षा न होने व मौसम के शुष्क रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी की आशंका जताई है।

धान की फसल में परेशानी- अंचल के किसानों, खासतौर से डबरा, भितरवार क्षेत्र के किसान खरीफ में धान की रोपाई अधिक करते हैं। धान के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। लेकिन इस बार कम वर्षा होने से धान की रोपाई अभी तक कम हो पाई है। चूंकि आगामी सात से आठ दिन तक वर्षा होने की संभावना कम है। इसलिए भी रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है। कृषि विभाग ने इस बार वर्षा की स्थिति को देखते हुए धान की बुवाई का लक्ष्य महज 95 हजार हैक्टेयर रखा है।

कृषि विशेषज्ञों ने दी सलाह

कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डा. शैलेंद्र सिंह कुशवाह के मुताबिक जिन किसानों ने फसल की बुवाई कर दी है, यदि जरूरत लग रही है तो उन्हें फसलों की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वैसे बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द, मूंग आदि की फसल कम पानी की और सूखा रोधी होती हैं। इनकी बुवाई 31 जुलाई तक कर सकते हैं। इसलिए उन किसानों को अभी इंतजार करना चाहिए, जिन्होंने बुवाई नहीं की है। इस बार मौसम विभाग का कम वर्षा होने का अनुमान है। इसलिए किसानों को कम पानी की फसलों की बुवाई ही करना चाहिए।

बजारा और दलहनी फसलें जल्द बोने वाले किसान परेशान

जिन किसानों जुलाई के पहले सप्ताह में वर्षा के बाद अपने खेतों में बाजरा सहित दलहनी फसल मसलन मूंग, उड़द तिल आदि की बुवाई कर दी थी। यह किसान काफी मुश्किल में हैं, क्योंकि फसल उपजने लगी है और वर्षा बंद हैं, साथ ही तापमान भी बढ़ रहा है। जिससे तीखी धूप की वजह से अंकुरित पौधे झुलस रहे हैं।

समाज को क्या हुआ है?

आखिर हमारे समाज को हो क्या गया है? यह सवाल अब किसी भावुक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि हर दिन सामने आती खबरों का सबसे स्वाभाविक निष्कर्ष बन चुका है। अखबार का हर नया पन्ना मानो इंसानियत के एक और टूटते हुए अध्याय का साक्षी बन रहा है। कहीं 13 वर्ष की मासूम दरिंदगी का शिकार होती है, कहीं तीन साल की बच्ची की चीखें सभ्यता के दावों को झुठला देती हैं, तो कहीं 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला भी हवस के अपराधियों से सुरक्षित नहीं रहती। इससे भी अधिक भयावह तब लगता है, जब हत्या की खबरें घर की चौखट के भीतर से आती हैं-पोता दादा का हत्यारा बन जाता है, बेटी मां की जान ले लेती है और रिश्तों की गरिमा स्वार्थ तथा क्रोध के आगे बिखर जाती है। यह केवल अपराधों की बढ़ती संख्या का प्रश्न नहीं है। यह उस सामाजिक चेतना के क्षरण की कहानी है, जिसने कभी परिवार, संस्कार और संवेदनाओं को भारतीय जीवन का सबसे मजबूत आधार बनाया था। आधुनिकता की चमक में कहीं नैतिकता का दीपक धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है, जब भगवान का घर भी अपराधियों की नजर से नहीं बच पाता। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में होने वाली चोरियां केवल दानपात्र से धन ले जाने की घटनाएं नहीं हैं। उस दानपात्र में पड़ा हर सिक्का किसी गरीब की श्रद्धा, किसी मां की मन्नत, किसी किसान की कृतज्ञता और किसी बुजुर्ग की आस्था का प्रतीक होता है। जब अपराधी उस विश्वास को भी लूटने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि संकट केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज के चरित्र का है। कलियुग का अर्थ केवल बुराई का बढ़ जाना नहीं है। हर युग अपने कर्मों से पहचाना जाता है। यदि समाज अपनी संवेदनाओं को पुनर्जीवित करे, परिवार अपने दायित्व को समझे और नागरिक अपने आचरण में नैतिकता को स्थान दें, तो अंधकार के बीच भी प्रकाश का मार्ग बनाया जा सकता है। भारत की असली ताकत उसकी संस्कृति, उसकी आस्था और उसके संस्कार हैं। इन्हें बचाना केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। तभी आने वाली पीढ़ियां यह कह सकेंगी कि कठिन समय में भी समाज ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने मूल्यों को फिर से जीवित कर लिया।

सकारात्मक संकेत... विकसित संस्कृति के विकास से बढ़ा आयकर का दायरा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
स्तंभकार

किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या उद्योगों की वृद्धि के साथ ही इस बात से भी होती है कि उसके नागरिक आर्थिक रूप से कितने जागरूक, जिम्मेदार और अनुशासित हैं। आज भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की लगातार बढ़ती संख्या इसी सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। निश्चित ही भारतीय जनसंख्या का यह कदम देश में विकसित होती वित्तीय संस्कृति, बढ़ती कर-अनुपालन की भावना और औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समाज का प्रतिबिंब है।

आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल होने की जानकारी इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है, जिसमेंकि एक ही दिन में 10 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह व्यवहार आर्थिक अनुशासन का परिचायक है और विकसित देशों की कर संस्कृति से मेल खाता है।

साथ ही भारत सरकार के उन प्रयासों को भी दर्शाता है, जिसमें कि भारत में पिछले एक दशक के दौरान कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल, प्री-फिल्ड रिटर्न, आधार-पैन एकीकरण, ऑनलाइन सत्यापन, फेसलेस असेसमेंट और त्वरित रिफंड जैसी व्यवस्थाओं ने करदाताओं की कठिनाइयों को काफी कम किया है। अब आईटीआर दाखिल करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। यही कारण है कि पहले जो लोग आयकर प्रक्रिया से दूरी बनाए रखते थे, वे भी अब औपचारिक कर व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

वस्तुतः आज भारत सरकार द्वारा नए आईटीआर फॉर्म में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ प्रकार के ट्रेडिंग लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य किए जाने से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इससे कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी और ईमानदार करदाताओं के लिए व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी।

कहना होगा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि का सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की प्रारंभिक अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.64 प्रतिशत और सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि यह बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का औपचारिक दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। प्रत्यक्ष कर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे स्वस्थ राजस्व स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे आय और लाभ पर आधारित होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक स्थिति को भी प्रतिबिंबित करते हैं।

यह परिवर्तन वस्तुतः इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय समाज में वित्तीय साक्षरता भी तेजी से बढ़ी है। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पूंजी बाजार में बढ़ती भागीदारी ने नागरिकों को अपनी आय और निवेश का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए आयकर रिटर्न भरना केवल कर भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंक ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वीजा, सरकारी निविदाओं तथा अनेक वित्तीय प्रक्रियाओं में आईटीआर की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अनेक ऐसे लोग भी नियमित रूप से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जिनकी कर देनदारी सीमित या शून्य है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुगतान प्रणाली, जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ढांचा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), औपचारिक रोजगार में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भी कर आधार को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नकदी आधारित लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से आर्थिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण मजबूत हुआ है, जिससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी बना है।

इस बढ़त के कारण से देश का राजस्व मजबूत हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका सीधा संबंध देश के विकास से है। सरकार को जितना अधिक प्रत्यक्ष कर प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक क्षमता उसके पास आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, रेलवे, सड़क, सिंचाई, डिजिटल नेटवर्क और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में निवेश करने की होगी। करदाता और विकास के बीच यह संबंध जितना मजबूत होगा, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी उतनी ही स्थायी होगी।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज आर्थिक विकास के साथ ही जिम्मेदार नागरिक, व्यापक कर आधार और स्वैच्छिक कर अनुपालन भी आवश्यक है। इस दृष्टि से 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न का समय से पहले दाखिल होना आज भारत की बदलती राष्ट्रीय मानसिकता का संकेत है। यह बताता है कि भारत का नागरिक अब आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ अपने आर्थिक दायित्वों के प्रति भी पहले से अधिक सजग हो रहा है। अब कहना यही होगा कि आयकर का बढ़ता दायरा भारत की बढ़ती आय, विस्तृत होती औपचारिक अर्थव्यवस्था, तकनीक आधारित सुशासन और आर्थिक शिक्षा के प्रसार का सम्मिलित परिणाम है। यह उस भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां कर भुगतान राष्ट्र निर्माण में साझेदारी के रूप में देखा जाने लगा है। यदि यही प्रवृत्ति आगे भी बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

अदालत की मर्यादा सर्वोपरि, पीड़ित की पीड़ा समझना भी उतना ही आवश्यक

कांतिलाल मांडोत
स्तंभकार

देश की सबसे बड़ी अदालत में मर्यादा भी सर्वोपरि और पीड़ित की पीड़ा को समझना भी उतना ही आवश्यक देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक का भी कर्तव्य है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा न्यायाधीशों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कागजात उछालना और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के भीतर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। अदालत तर्क और कानून की भाषा समझती है, आक्रोश और अपमान की नहीं। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला स्वयं कानून और शिष्टाचार की सीमाएं लांघने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है। वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का भी अधिकारी माना जाता है। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा होता है। इसलिए अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखें। असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन असहमति और अभद्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति और न्यायिक परंपरा की पहचान है।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने वकील की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना की कठोर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति संभवतः अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में है तथा उसकी हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की मानवीय संवेदना को भी सामने लाता है। कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझने और न्याय के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखने की व्यवस्था भी है।

वास्तविकता यह है कि न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, संघर्ष या अन्याय का बोझ लेकर आता है। वर्षों तक मुकदमे लड़ने, आर्थिक बोझ उठाने और बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यह टूटन कभी-कभी हताशा और असंतुलित व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया जाए, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि उसके पीछे पीड़ा और निराशा का एक लंबा इतिहास भी हो सकता है।

न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी संवेदनशीलता भी है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न्याय केवल आदेश सुनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास भी पैदा करता है कि अदालत ने व्यक्ति की बात पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

यह भी सच है कि न्याय में विलंब, लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते मुकदमों का बोझ कई लोगों में निराशा पैदा करता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक हैं। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, तो निराशा और असंतोष की स्थितियां भी कम होंगी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है।

इस घटना ने एक और संदेश दिया है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने में सभी की समान जिम्मेदारी है। यदि अदालत में अनुशासन समाप्त हो जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसका नुकसान अंततः आम नागरिक को ही होगा। इसलिए चाहे वह वरिष्ठ अधिवक्ता हों, नए वकील हों या स्वयं पक्षकार, सभी को यह समझना होगा कि अदालत में शब्दों का चयन, व्यवहार की मर्यादा और कानून के प्रति सम्मान सर्वोपरि है। दूसरी ओर न्यायपालिका की उदारता भी सराहनीय है। यदि अदालत चाहती तो अवमानना की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने संयम दिखाया और कठोर दंड देने के बजाय मामले को वहीं समाप्त करना उचित समझा। यह निर्णय बताता है कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा का संतुलित स्वरूप है। हालांकि इस उदारता का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का साहस करे। कानून का सम्मान हर परिस्थिति में अनिवार्य है। लोकतंत्र में न्यायपालिका अंतिम आशा होती है। जब प्रशासन, व्यवस्था और अन्य संस्थाओं से निराश व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो उसके मन में उम्मीद की आखिरी किरण बची होती है। इसलिए अदालतों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने खड़ा हर व्यक्ति केवल एक केस नंबर नहीं, बल्कि अपने जीवन की किसी गहरी समस्या से जूझता हुआ इंसान है। उसकी बात सुनते समय कानून के साथ मानवीय संवेदना भी बनी रहनी चाहिए। इस घटना से देश को दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अदालत की गरिमा किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में अपशब्द, आक्रोश और अभद्र व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। दूसरी, न्याय व्यवस्था को लोगों की पीड़ा, मानसिक तनाव और संघर्ष को भी समझना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल निर्णय देने का नाम नहीं, बल्कि समाज में विश्वास बनाए रखने की प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसकी प्रतिष्ठा पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। वहीं, अदालत की चौखट पर आने वाला हर व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर आता है। इसलिए आवश्यक है कि एक ओर अधिवक्ता और पक्षकार अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को समझें, तो दूसरी ओर न्याय व्यवस्था भी हर पीड़ित की व्यथा को महसूस करते हुए कानून और संवेदना के बीच संतुलन बनाए रखे। यही संतुलन भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है और यही लोकतंत्र की स्थायी पहचान भी।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

मर्दों को कम होता है UTI , लेकिन हो तो कई गुना खतरनाक होने की आशंका

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) की समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। वहीं पुरुषों में 40 वर्ष की आयु के बाद यह की समस्या हो सकती है। पुरुषों में यह कम होती है, लेकिन अगर समस्या हुई है तो इसे अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है, जिसके लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार महिलाओं में यूरेथ्रा (टॉयलेट की नली) पुरुषों के यूरेथ्रा से काफी छोटी होती हैं। इस वजह से बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए पुरुषों में इंफेक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

हॉवर्ड हेल्थ के अनुसार पुरुषों में होने वाला UTI अक्सर किसी न किसी हेल्थ कंडीशन से जुड़ा होता है। यही कारण है कि इसे सामान्य UTI की तुलना में ज्यादा गंभीर माना जाता है। यदि इंफेक्शन का समय पर इलाज न किया जाए, तो इंफेक्शन किडनी तक फैल सकता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। कुछ मामलों में यह ब्लड इंफेक्शन (सेप्सिस) जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा हो सकती है।

पुरुषों में UTI की समस्या मेडिकल कारणों जैसे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, ब्लैडर में स्टोन या किडनी स्टोन के कारण हो सकते हैं और इन्हीं कारणों से इसे अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है।नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ-साथ कई पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट यूरेटर पर दबाव डाल सकता है, जिससे यूरेनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। यूरिन के रुकने से बैक्टीरिया आसानी से बढ़ने लगता है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैडर स्टोन की परेशानी अगर शुरू हो जाए तो यूरिन के सामान्य प्रवाह बाधित हो जाती है। ऐसी स्थिति होने पर यूरिन लंबे वक्त तक ब्लैडर में जमा रहता है, जिस वजह से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और UTI का कारण बन सकते हैं। हॉवर्ड हेल्थ के अनुसार जिन पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की समस्या है, उन्हें कैफीन और अल्कोहल का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। वहीं डॉक्टर द्वारा बताई गई कुछ दवाएं लेने से यूरिन फ्लो को ठीक करने में मदद मिल सकती है, जिससे ब्लैडर में यूरिन कम जमा होगा और इंफेक्शन की संभावना भी कम हो जाएगी। समय पर पहचान और इलाज से इंफेक्शन को गंभीर होने से रोका जा सकता है। ध्यान रखें कि यदि यूरिन पास करने के दौरान जलन, बार-बार यूरिन आने की इच्छा या यूरिन पास करने के समय दर्द जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

निशाना

ये तमाशा देखिए..!

मनोज साहू 'निडर'

ये हताशा ये निराशा देखिए।
थामकर सॉसें, जरा-सा देखिए।
रोटियाँ मयस्सर नहीं मजदूर को
श्वान को रबड़ी- बताशा देखिए।
बूढ़ी होती डिग्रियों को मिल रही
रोज़ ही ताज़ा दिलासा देखिए।
सच छुपाने की कवायद में यहाँ,
नित नया होता खुलासा देखिए।
जिम्मेदारी चुप्पियाँ ओढ़े खड़ी
आदमी बैठा ठगा-सा देखिए।
देवता भी मौन बैठे रह गए
लुट गई श्रद्धा, तमाशा देखिए।

वायरल कंटेंट

छह पीढ़ियों से एक ही चूल्हे में बनता है 83 सदस्यों का खाना, प्यार से रहता है पूरा परिवार

आज के दौर में जहां संयुक्त परिवार धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और ज्यादातर लोग छोटे परिवारों में रहना पसंद कर रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश का एक परिवार अपनी अनोखी जीवनशैली के कारण चर्चा में है। अनंतपुर जिले के कुरलपल्ली गांव में रहने वाला नागप्पा परिवार इस बात का उदाहरण है कि आपसी समझ, सहयोग और विश्वास के दम पर बड़ा परिवार भी खुशी-खुशी एक साथ रह सकता है।

इस परिवार में कुल 83 सदस्य हैं, जो छह पीढ़ियों से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि सभी लोग चार अलग-अलग मकानों में रहते हैं, लेकिन उनका रहन-सहन और पारिवारिक व्यवस्था आज भी एक संयुक्त परिवार की तरह ही है। घर के बड़े-बुजुर्ग पूरे परिवार का मार्गदर्शन करते हैं और हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता है। परिवार में दादा-दादी, माता-पिता, बहुएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी मिलकर घर और कारोबार की जिम्मेदारियां संभालते हैं।

इस परिवार की सबसे खास बात इसकी रोजाना की दिनचर्या है। हर सुबह सभी बड़े सदस्य एक साथ बैठकर चाय या कॉफी के साथ पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इसी दौरान तय किया जाता है कि कौन खेती का काम देखेगा, कौन घर की जिम्मेदारी संभालेगा और दिनभर के जरूरी काम कैसे पूरे किए जाएंगे। इस व्यवस्थित तरीके से काम बांटने की वजह से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और सभी मिलकर जिम्मेदारियां निभाते हैं।

चार मकानों के बावजूद पूरे परिवार का भोजन एक ही रसोई में तैयार किया जाता है। राशन से लेकर सब्जियों की व्यवस्था सामूहिक रूप से होती है, जबकि परिवार की महिलाएं मिलकर सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती हैं। साथ बैठकर भोजन करना यहां की सालों पुरानी परंपरा है, जिसे परिवार आज भी पूरी श्रद्धा से निभा रहा है। परिवार की आय का स्रोत केवल खेती नहीं है। कृषि के साथ-साथ यह परिवार परिवहन का व्यवसाय भी करता है। परिवार के पास कई बसें हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में संचालित होती हैं। परिवार की पूरी कमाई एक शेयर व्यवस्था में रखी जाती है और जरूरत के अनुसार खर्च की जाती है। यहां व्यक्तिगत कमाई से ज्यादा सामूहिक भलाई को महत्व दिया जाता है।

मार्केट वॉच

बाजार में तेजी के आसार... इसी महीने आ सकते हैं 15 हजार करोड़ के IPO

भारत के प्राइमरी मार्केट में तेजी आने लगी है। पिछले दो महीनों से यह लगातार बेहतर हुई है। मनीकंट्रोल के अनुसार बताया अगले हफ्ते SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO खुलने वाला है। जुलाई के आखिर तक पांच और IPO मार्केट में आ सकते हैं। इन कंपनियों का कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। इस लिस्ट में कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स , मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स, जुनिपर ग्रीन एनर्जी, लोहिया कॉर्प और मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज शामिल हैं।

यह सुधार धीरे-धीरे हुआ है। जून में 2,718 करोड़ रुपये के सात IPO मार्केट में आए थे। जुलाई में अब तक तीन इश्यू लॉन्च हो चुके हैं - नैक पैकेजिंग, कुसुमगर और लेजर पावर एंड इंफ्रा। अगले हफ्ते SBI फंड्स मैनेजमेंट और अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड दोनों का पब्लिक इश्यू खुलने वाला है। भारत की टॉप 10 कोल माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में से एक कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स के जल्द ही लगभग 500-600 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। तमिलनाडु की डेयरी कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स के जुलाई के आखिर तक लगभग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है। ज्ञ कैपिटल ग्रुप की बैकिंग वाली जुनिपर ग्रीन एनर्जी भी जल्द ही अपना IPO लॉन्च करेगी। हालांकि, इश्यू का साइज पहले प्लान किए गए 3,000 करोड़ रुपये से घटाकर अब 1,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट बनाने वाली ग्लोबल कंपनी लोहिया कॉर्प एक 'प्योर ऑफर-फॉर-सेल' इश्यू लॉन्च करेगी। इससे लगभग 500 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल्स चेन चलाने वाली मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज के भी 9,500 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च करने की संभावना है। इन पांचों IPO से कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है।

बेंगलुरु की टोनबो इमेजिंग और मध्य प्रदेश की फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सिम्बायोटेक फार्मालैब भी उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जो जुलाई के आखिरी और अगस्त के पहले हफ्ते में मार्केट में उतरने की योजना बना रही हैं।

न्यूज विंडो

मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तय

गंजबासौदा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंजबासौदा के तत्वावधान में आगामी 15 जुलाई को भोपाल में आयोजित होने वाली साइकिल रैली एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारियों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसजन 15 जुलाई को प्रातः 10 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नितिन दुबे ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में आयोजित मुख्यमंत्री निवास घेराव में गंजबासौदा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बैठक में मुख्य रूप से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संतोष शर्मा, रवि तिवारी, सत्यप्रकाश सेन, जगदीश सुहाने, कल्याण सिंह नागौरी, सुनील बाबू पिंगले, राजकुमार सेन, नगर कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष भगवानदास शर्मा, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष जगदीश व्यास, पार्षद राहुल ठाकुर, मनी अहिरवार, जिला कांग्रेस महासचिव रविंद्र रघुवंशी, मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव अपूर्व जैन, अनिल पाठक, आदिल खान, लालाराम चंदेल, प्रणव मिश्रा, युवा कांग्रेस नेता हर्ष शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सफाई अपनाओ-बीमारी भगाओ अभियान में दिया अच्छे स्वास्थ्य का संदेश

गंजबासौदा। स्थानीय सेंट एस.आर.एस. पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में ÷सफाई अपनाओ-बीमारी भगाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से घर-घर स्वच्छता का संदेश पहुंचाकर लोगों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक करना रहा। मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. नेमा ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता सबसे जरूरी है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में घरों में बेकार पड़े कूलरों, गमलों, पुराने टायरों तथा आसपास के गड्ढों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू व मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही हमें स्वस्थ रख सकती है और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम पांच परिवारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प ले। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं ने स्वच्छता की सामूहिक शपथ लेकर अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य उमेश चंद्र यादव, एनएसएस बालक इकाई कार्यक्रम अधिकारी के.पी. सिंह चौहान, बालिका इकाई कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रजनी गुप्ता, सुश्री प्रियंका अग्रवाल, सोनू राय, सविता यादव, अंचल जैन सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

कलेक्टर ने आबकारी विभाग के पदोन्नत अधिकारी-कर्मचारियों का किया सम्मान

नर्मदापुरम। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम में आबकारी विभाग के पदोन्नत अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ने पदोन्नत अधिकारियों और कर्मचारियों को स्टार एवं फित्ती लगाकर उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर रघुवीर प्रसाद निमोदा को आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर तथा गोपाल रघुवंशी, मनोज रघुवंशी, मदन रघुवंशी, राजेश भारती, राजेश गौर और दुर्गेश पठारिया को मुख्य आरक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर सम्मानित किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि पदोन्नति केवल जिम्मेदारियों में वृद्धि नहीं, बल्कि अधिकारी-कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य, निष्ठा और समर्पण का सम्मान भी है। उन्होंने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे नई जिम्मेदारियों का ईमानदारी, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में योगदान देंगे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पदोन्नत साथियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बिजली के खंभों पर लगे फ्लेक्स पर विवाद, नियमों के उल्लंघन के आरोप

अमरकंटक। सावन माह में लगने वाले एक माह के धार्मिक मेले से पहले अमरकंटक नगर परिषद क्षेत्र में बिजली के खंभों पर लगाए जा रहे फ्लेक्स और होर्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिना नियमानुसार अनुमति और राजस्व शुल्क जमा किए सार्वजनिक विद्युत खंभों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में लगभग चार से पांच दिन पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका सवाल है कि यदि फ्लेक्स वैध हैं तो संबंधित अनुमति और राजस्व वसूली का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, और यदि अनुमति नहीं ली गई है तो इन्हें तत्काल हटाकर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। नियमों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, शासकीय संपत्ति अथवा विद्युत खंभों पर विज्ञापन, बैनर या फ्लेक्स लगाने के लिए संबंधित विभाग की अनुमति तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान आवश्यक होता है। बिना अनुमति लगाए गए फ्लेक्स और होर्डिंग को अवैध माना जा सकता है तथा संबंधित निकाय को उन्हें हटाने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार होता है।

जिम्मेदारों ने सील कराया पूरा गेहूं, बोले- बदलकर भेजेंगे दूसरा, पड़ताल जारी

टीकमगढ़ में राशन दुकान पर गेहूं के बोरे से निकली हड्डियां, हितग्राहियों में मचा हड़कंप

टीकमगढ़। दोपहर मेट्रो

अबतक आपने उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को घुन लगा और खराब राशन मिलने के मामले तो कूब देखे और सुने होंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक उचित मूल्य की दुकान में वितरित होने वाले राशन के बोरे में जो निकला है, उसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिले के बुड़ेरा में स्थित राशन दुकान पर कंकाल युक्त राशन मिलने का मामला सामने आया है।

नन्ही टेहरी के उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों को राशन वितरण के लिए जैसे ही बोरी खोली गई उसमें सिर की हड्डी के साथ ही दो हड्डियां निकली। यह देखकर पहले तो हितग्राही डर गए। फिर उन्होंने ये राशन लेने से मना कर दिया। वहीं, मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी वितरण केंद्र पहुंचे और बोरे की पड़ताल करने के बाद दुकान पर आए पूरे राशन को सील करा दिया है। अधिकारियों ने दूसरा राशन पहुंचाने की बात कही है। सोमवार को ग्राम लक्ष्मणपुरा के लोग राशन लेने के लिए नन्ही टेहरी की उचित मूल्य की दुकान पर गए थे। लक्ष्मणपुरा की दुकान बंद होने से इन लोगों को नन्ही टेहरी की दुकान से राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी। राशन लेने पहुंचे कोमल लोधी और परम लोधी के सामने जैसे ही गेहूं की बोरी खोली गई और उसमें हड्डियां दिखाई दी। इसमें किसी जानवर के सिर और पैर की हड्डियां थी। ये देखकर पहले तो हितग्राही डर गए। फिर पूरी बोरी को जमीन पर खाली की गई। गेहूं में जानवर की हड्डियां मिलने पर हितग्राहियों ने इसे लेने से इंकार कर दिया। इस गंभीर मामले को लेकर तत्काल ही प्रशासन अलर्ट हुआ और खाद्य विभाग की टीम को भेजा गया। इसके बाद इस राशन का वितरण बंद करा दिया गया है। यहां पर पूरा राशन वापस कर दूसरा माल भेजा जाएगा।

पहले दमोह से आया था घुना गेहूं, इसके पहले जबलपुर से सड़ा चावल

विदित हो कि, दो महीने पहले ही जिले में दमोह से खराब गेंहू भेजा गया था। इसे प्रशासन ने वापस कर दिया था। वहींस दो साल पहले 18000 क्विंटल सड़ा चावल जबलपुर और रीवा से यहां पहुंचाया गया था। ये चावल अब भी जिले के गोदामों में बंद है और प्रशासन बार - बार इसे वापस करने पत्राचार कर रह है। अभी उस चावल का मामला सही नहीं हो सका कि, अब इस हड्डी युक्त गेहूं ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े करना शुरु कर दिए हैं।

कहां का माल है पता कर वापस करेंगे

मामले की जांच में जुटे टीकमगढ़ के खाद्य निरीक्षक सार्थक तिवारी का कहना है कि, नन्ही टेहरी की राशन दुकान के पूरे माल को वापस सील करा दिया गया है। इसे वापस कर हितग्राहियों के लिए दूसरा माल भेजा जाएगा। नान से पता किया जाएगा कि, ये माल कहां से आया था। वहां माल वापस कर उसकी शिकायत की जाएगी। गेहूं में भेड़ का सिर और पैर की हड्डियां होना बताई जा रही है।

जावरा में सिस्टम से नाराज होकर 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा किसान, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

रतलाम। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभाग के ग्राम नागदी में एक किसान भूमि के सही सीमांकन न होने से नाराज होकर गांव में स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की जानकारी लगते ही गांव में हड़कंप मच गया और प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे नीचे नीचे उतारने का खासा प्रयास करते रहे। पर किसान की मांग थी कि, जबतक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो नीचे नहीं उतरेगा। इस दोरान लोगों की खासा भीड़ क्षेत्र में इकट्ठी हो गई। घंटों इलाके में हाईवोल्टेज ड्रामा जारी रहा। बातचीत के दौरान टंकी पर चढ़े 49 वर्षीय किसान मुकेश मालवीय ने अफसरों से कहाकि, उसकी मां प्रभु भाई पति नागूलाल मालवीय की भूमि है। इस भूमि के नपती के लिए वह तीन बार तहसील कार्यालय में आवेदन कर चुका है। तीनों बार पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) ने मौके पर जाकर भूमि का नाप किया, परंतु उन्होंने सही नहीं किया। इसके कारण तीनों बार उसकी भूमि अलग-अलग तरीके से कम होती जा रही है, जिससे उसकी जमीन समाप्त होने का खतरा है। इसी मांग को लेकर वो पानी की टंकी पर चढ़ा है। उसके खेत के पड़ोसी भगत लाल पाटीदार ने भूमि के सीमांकन के बाद वहां चारदीवारी खींचना शुरू कर दी। इस बात की सूचना उसने पुलिस के 112 नंबर पर दी। पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंचकर उसे धमकाया और कहा कि, बार-बार पुलिस को क्यों परेशान करते हो, यह तुम्हारा जमीन का मामला है। उसकी जमीन सीमांकन में आई है, इसलिए वो बाउंड्री लगा रहा है।

बोला-जब तक मांग पूरी नहीं होगी, नीचे नहीं उतरूंगा

फरियादी मुकेश का कहना है कि, पुलिस ने भी उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए अब आखिरी बात मनवाने के लिए वो पानी की टंकी पर चढ़ा है। उसने कहा कि, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा।

अफसरों के छूटे पसीने

किसान के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिसे किसान को समझने में 2 घंटे का समय लग गए और उसके बाद आखिर में ग्रामीण जनों की गारंटी पर किसान को टंकी से नीचे उतारा गया। नीचे उतरने के बाद किसान के साथ पटवारी और राजस्व निरीक्षक खेत की ओर गए और मौके पर जाकर स्थिति को समझा।

ई-टोकन प्रणाली से गुस्साए किसानों ने कलेक्टोरेट में फाड़ दिया ज्ञापन

रतलाम। दोपहर मेट्रो

जिले के किसान खाद वितरण की ई-टोकन प्रणाली से परेशान हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और जिला युवा कांग्रेस के बेनर तले ई-टोकन प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार रामचंद्र पांडे और डीडीए भगवानसिंह अर्गल के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए किसानों ने बताया कि बोवनी के बाद खाद लेने के लिए ई-टोकन बुक करना पड़ता है, जो उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। किसानों के अनुसार, पोर्टल पर उर्वरक का निर्धारण फसल की आवश्यकता के आधार पर न्यायसंगत नहीं है। अधिकारियों से चर्चा के दौरान कोई उचित जवाब नहीं मिलने और समस्याओं में सुधार नहीं होने पर किसानों ने ज्ञापन वहीं फाड़ दिया और चले गए।

प्रदर्शन करते हुए किसान सोमवार दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचे किसानों का कहना था कि मक्का जैसी फसल के लिए केवल यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन पोर्टल पर एनपीके, एसएसपी या डीएपी भी लेना अनिवार्य दर्शाया जा रहा है। इसके बिना बुकिंग आगे नहीं बढ़ती। रतलाम के गोदामों में खाद पर्याप्त होने के बावजूद, पोर्टल पर यह उपलब्ध नहीं दिखता, जिससे किसानों को 50-55 किलोमीटर दूर के गोदामों के टोकन मिल रहे हैं। किसानों ने ई-टोकन सॉफ्टवेयर में सुधार करने और खाद 4-7 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराने की मांग की है।

ज्ञापन के दौरान लक्ष्मणसिंह डिंडोर, युवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष देवेंद्रसिंह सेजावता, राष्ट्रीय किसान महासंघ जिलाध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय, किसान नेता राजेश पुरोहित, जनपद सदस्य मानवेंद्रसिंह लूनेरा, महेंद्रसिंह, समरथलाल पाटीदार, गोपाल गुर्जर, मांगीलाल मालवीय, जितेंद्रसिंह, देवीलाल जाट, गौरव प्रजापत आदि कई किसान मौजूद थे।

अनुशासनहीनता और कदाचार के आरोप में बीईओ आशा निलंबित

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

संभागायुक्त नर्मदापुरम संभाग श्रीकांत बनोट ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) केसला आशा मौर्य को कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई। जारी आदेश के अनुसार, आशा मौर्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग, नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। संभागायुक्त द्वारा जारी इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जलभराव पर सतत निगरानी रखें अधिकारी किसानों को समय पर मिले खाद-कलेक्टर

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने वर्षाकाल को देखते हुए जिले में जलभराव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि किसी भी क्षेत्र में जलभराव या आपात स्थिति बनने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिक लंबित शिकायतों वाले विभागों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का संतोषजनक और समयबद्ध निराकरण करने तथा नॉन-अटेंडेड शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने किसानों को खाद की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों में पर्याप्त खाद का भंडारण रहे और जहां खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को वितरण नहीं किया जा रहा है, वहां समिति प्रबंधकों के विरुद्ध नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निराश्रित गौवंश के प्रबंधन को लेकर भी कलेक्टर ने सभी अनुविभागों में विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थायी और अस्थायी गौशालाओं में निराश्रित गौवंश को स्थानांतरित कर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का चिन्हांकन संबंधित एसडीएम से समन्वय कर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में जवाब-दावा प्रस्तुत करने, लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने और जिला अभियोजन अधिकारी से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने संयुक्त कलेक्टर को रिट याचिकाओं और अन्य न्यायालयीन मामलों की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने, संभागायुक्त कार्यालय से प्राप्त समय-सीमा पत्रों का दो दिन में निराकरण करने तथा अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर प्रति शिकायत जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर अनिल जैन एवं राजेश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मेट्रो एंकर — दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू

11,595 पशुपालक परिवारों तक पहुंचेगी टीम, करेंगे जागरुक

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण का सोमवार को शुभारंभ किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से विभागीय दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर अनिल जैन, राजेश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर डॉ. बबीता राठौर, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. शैलेंद्र नेमा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 13 से 18 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के सभी सात विकासखंड– नर्मदापुरम, माखननगर, पिपरिया, बनखेड़ी, सोहागपुर, सिवनी मालवा और केसला में विभागीय दल घर-घर जाकर पशुपालकों से संपर्क करेंगे। अभियान का लक्ष्य जिले के 11,595 पशुपालक परिवारों तक पहुंचना है। अभियान के दौरान प्रत्येक सर्वेयर प्रतिदिन 10 पशुपालक परिवारों से मिलकर उन्हें वैज्ञानिक पशुपालन, पशुओं के संतुलित पोषण, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य प्रबंधन तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा।

नस्ल सुधार और वैज्ञानिक पशुपालन पर विशेष जोर

अभियान के तीसरे चरण में विशेष रूप से ऐसे पशुपालकों को शामिल किया गया है, जिनके पास 3 से 4 गौवंश या भैंसवंशीय पशु हैं। विभागीय अधिकारी पशुपालकों को पशु नस्ल सुधार, हरे चारे के बेहतर प्रबंधन, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, नियमित टीकाकरण और वैज्ञानिक पशुपालन की आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालन को अधिक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।

वन विभाग की कार्रवाई: सागौन की लकड़ी से लदी 6 साइकिलें जब्त

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

मानसून आते ही वन माफिया और शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और घने जंगलों में मानसून के दौरान आवागमन कम होने का फायदा उठाकर वन माफिया हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं। इमारती लकड़ी की तस्करी तेजी से बढ़ रही है, इसी बीच तेंदूखेड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाथीडोल बीट भाग 2 में बीती रात करीब 10 बजे गश्त के दौरान वन विभाग ने लकड़ी तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए सागौन की बहुमूल्य लकड़ी से लदी 6 साइकिलें जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान वन अमले को आता देख लकड़ी चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रेयांश जैन ने बताया कि विभाग को रात्रि में सूचना मिली थी कि हाथीडोल वन बीट भाग 2 में कुछ लोग अवैध रूप से सागौन की

लकड़ी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में वन विभाग का दल तत्काल रात्रि गश्त पर रवाना हुआ। वन अमले की मौजूदगी का आभास होते ही लकड़ी चोर अपनी साइकिलें और उन पर लदी बहुमूल्य सागौन की लकड़ी छोड़कर जंगल के अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले।

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देखा कि 6 साइकिलों पर सागौन की लकड़ी लदी हुई थी, जिसे चौपाटी एवं पाया बनाने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। वन अमले ने लकड़ी एवं साइकिलों को जब्त कर तेंदूखेड़ा वन परिसर लाया गया है। मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज कर लिया गया है तथा उनकी पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है जिनकी टीम अब तलाश कर रही है।

इस कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रेयांश जैन, डिप्टी रेंजर बृजेश कौल, वनरक्षक संदीप ठाकुर, वनरक्षक अभिनय झारिया तथा वाहन चालक सुरेश केवट सहित वन विभाग का अमला शामिल रहा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त एवं निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज विंडो

विहिप-बजरंग दल ने 51 पौधे रोपकर किए विविध सेवा कार्य

तेन्दूखेड़ा। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा 5 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा सप्ताह का सफल आयोजन किया गया। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर, मठ-मंदिरों एवं नदी घाटों की स्वच्छता, पौधरोपण तथा धर्म, राष्ट्र, गौ-रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरण का संकल्प लिया गया। सेवा सप्ताह के समापन अवसर पर प्रखण्ड अध्यक्ष विदित सिंह तौमर, प्रखण्ड मंत्री उदय सेन एवं प्रखण्ड संयोजक तेजी सिंह लोधी के नेतृत्व में हरई ग्राम स्थित श्री हनुमान मड़िया परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर पौधरोपण किया गया तथा पौधों की सुरक्षा के लिए अस्थायी सुरक्षा घेरे भी बनाए गए। इस अवसर पर प्रखण्ड उपाध्यक्ष मनीष साहू, सह मंत्री राजेश केवट, सह संयोजक मोनू गोप, विशेष संपर्क प्रमुख सिद्धार्थ मोदी, धर्म प्रसार प्रमुख लक्ष्मण यादव, गौ-रक्षा प्रमुख लक्ष्मण घोषी, सेवा प्रमुख वीरू महोबिया, बलोपासना प्रमुख सौरभ घोषी, नगर उपाध्यक्ष परषोत्तम रजक, आदित्य खटीक, राजवीर घोषी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन द्वारा सेवा सप्ताह के दौरान नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 पौधों का रोपण किया गया। भटरिया एवं पठाघाट मुक्तिधामों के साथ तारादेही, बगदरी तथा अन्य ग्राम समितियों के सहयोग से निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किया गया।

जिले की बेटी के सपनों को मिला पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल का सहारा

नरसिंहपुर। जनसेवा को अपनी प्राथमिकता मानने वाले पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने एक बार फिर संवेदनशील पहल करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की दो बेटियों की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व उठाने का निर्णय लिया। उनकी इस पहल की जिलेभर में सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार, नरसिंहपुर निवासी छात्रा रंजना अपने परिजनों के साथ पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल से मिलने पहुंची इस दौरान बिटिया ने परिवार की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई जारी रखने में आ रही कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया। छात्रा ने बताया कि उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उसका सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का है, लेकिन आर्थिक अभाव उसके सपनों के बीच बड़ी बाधा बन रहा है। छात्रा की बात सुनते ही जालम सिंह पटेल ने तत्काल विद्यालय प्रबंधन से चर्चा कर उसकी समस्याओं के समाधान की पहल की। उन्होंने न केवल रंजना, बल्कि उसकी बहन की शिक्षा का पूरा खर्च स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया। साथ ही छात्रा को लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और आर्थिक चिंता से मुक्त होकर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया पूर्व राज्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति कभी भी उनके सपनों में बाधा नहीं बननी चाहिए। समाज के सक्षम लोगों का दायित्व है कि वे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें, क्योंकि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य का सबसे मजबूत आधार है विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि छात्रा की प्रतिभा और परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व राज्यमंत्री ने तत्काल दोनों बहनों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारियों को लेकर की चर्चा

नरसिंहपुर। जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम के प्रथम नगर आगमन को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों, पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं को संगठन के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे वे संगठनात्मक गतिविधियों और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर सकें बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और अनुशासित कार्यशैली से होती है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया उक्त बैठक में मोर्चा जिला प्रभारी गुरुप्रसाद धुर्वे,भाजपा जिला मंत्री दुर्गेश नंदनी उइके अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामकुमार ठाकुर सहित मोर्चा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शहडोल जिले के जैतपुर क्षेत्र का मामला

समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस, ऑटो में प्रसव के बाद महिला की हुई मौत

शहडोल। दोपहर मेट्रो

जैतपुर थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर 108 एंबुलेंस नहीं पहुंचने के कारण महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया और अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार जैतपुर थाना क्षेत्र के गलहथा गांव के मौहार टोला निवासी 22 वर्षीय जयमंती पाण्डो, पत्नी रामकुमार पाण्डो, को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। आरोप है कि कई घंटे इंतजार करने के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों ने गांव से एक ऑटो की व्यवस्था कर महिला को जैतपुर अस्पताल के लिए रवाना किया। रास्ते में ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मां और नवजात का उपचार शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलने पर जैतपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर

पीएम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बुढार डॉ. सचिन कारकुर ने बताया कि गर्भवती की स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही थी। बीच में महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके अथवा रिश्तेदारी चली गई थी, जिससे कुछ आवश्यक जांच नहीं हो सकीं। अब तक उसकी तीन प्रसव पूर्व जांच हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के विलंब से पहुंचने के कारण रास्ते में प्रसव हुआ।

दी है। थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि महिला नवविवाहित थी। नियमानुसार मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। महिला की मौत किन कारणों से हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को स्वयं क्षेत्र का दौरा कर परिजनों से चर्चा करेंगे तथा संबंधित सीएचओ और स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक भी बुलाई गई है।

कलेक्टर ने की कार्रवाई

3 तहसीलदारों समेत 8 अधिकारियों-कर्मियों पर लगाया जुर्माना

छतरपुर। दोपहर मेट्रो

जिला प्रशासन ने लापरवाही करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा (टीएल) पत्रों की समीक्षा बैठक में सख्त रुख दिखाया है। बैठक के दौरान शासकीय कार्यों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने करारी फटकार लगाई है। उन्होंने समय-सीमा से बाहर होने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए तीन तहसीलदारों, दो नायब तहसीलदारों और तीन पंचायत सचिवों पर सीधे आर्थिक जुर्माना (पेनल्टी) ठोक दिया है। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि लोक सेवा गारंटी और जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा पार कर चुके प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दोषी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर पेनल्टी लगाई है। वहीं, पठा के नायब तहसीलदार पर 1000 रुपये व ज्यौराहा के नायब तहसीलदार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि राजनगर, छतरपुर और गौरिहार के तहसीलदारों पर 500-500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है और पठापुर, गौरैया एवं खंडवन ग्राम पंचायत के सचिवों पर भी 500-500 रुपये का जुर्माना लगा है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने आगामी भारी बारिश के मौसम के दृष्टिगत निर्माण विभागों (पीडब्ल्यूडी, आरईएस, पीआईयू आदि) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों, पुलों और पुलियों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अति वर्षा के पूर्व ही आवश्यक मरम्मत और तैयारियां सुनिश्चित करें।

19 पेटी शराब जब्त, तस्कर फरार

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

क्षेत्र में देर-रात भगवती मानव कल्याण संगठन की सूचना पर तारादेही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरी एक कार जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार भगवती मानव कल्याण संगठन के तारादेही सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने शनिवार रात बम्होरी तिगड्डा क्षेत्र में एक संदिग्ध सफेद रंग की कार में अवैध शराब ले जाए जाने की सूचना तारादेही पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और हुंडई वरना कार जो इंदौर पासिंग की है कार की तलाशी ली गई तो 19 पेटी शराब बरामद हुई। तारादेही थाना प्रभारी आलोक तिरपुड़े ने बताया कि वाहन से 19 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.24 लाख रुपये है। साथ ही लगभग 3 लाख रुपये कीमत की कार भी जब्त कर ली गई है पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(2) के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

खामखेड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्य उल्टी-दस्त से हुए बीमार, उपचार जारी

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

ग्राम खामखेड़ा में एक ही परिवार के चार सदस्यों के अचानक उल्टी-दस्त से बीमार होने का मामला सामने आया है। सभी को परिजनों द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक की निगरानी में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

उपचाररत मरीजों में सतीश सेन (22 वर्ष) पिता परमलाल सेन, सुषमा सेन (40 वर्ष) पत्नी परमलाल सेन, आराधना सेन (20 वर्ष) पत्नी सतीश सेन तथा रानू सेन (17 वर्ष) पिता परमलाल सेन शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि रविवार रात परिवार के सभी सदस्यों ने घर पर दाल-चावल का भोजन किया था। इसके बाद सोमवार सुबह एक-एक कर चारों को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल बना, हालांकि गांव के अन्य लोगों ने बताया कि फिलहाल यह समस्या केवल इसी परिवार तक सीमित है। ग्रामीणों के अनुसार पूरे खामखेड़ा गांव में किसी अन्य व्यक्ति में उल्टी-दस्त जैसी शिकायत सामने नहीं आई है और गांव में किसी प्रकार के संक्रमण या सामूहिक बीमारी जैसी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, ताजा एवं स्वच्छ भोजन करने तथा उबला या शुद्ध पेयजल का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही, उल्टी-दस्त जैसे लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मामला भोजन के बाद उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि बीमारी के वास्तविक कारणों की पुष्टि चिकित्सकीय जांच के बाद ही हो सकेगी।

मेट्रो एंकर

शासकीय स्कूलों में सुविधाओं के अभाव में घटती छात्र संख्या से बंद हो रहे स्कूल

इस शिक्षा सत्र में तीन और जर्जर प्राथमिक स्कूलों पर लटके ताले

सागर/बीना। दोपहर मेट्रो

शिक्षा के अधिकार और सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के दावों के बीच क्षेत्र में शासकीय स्कूलों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कहीं स्कूल भवन ही उपलब्ध नहीं हैं, तो कहीं जर्जर भवन के चलते अभिभावकों ने बच्चों के नाम कटा लिए हैं, जिससे दर्ज संख्या शून्य हो गई है और इस शिक्षा सत्र में 3 प्राथमिक स्कूलों में ताले डल गए हैं।

जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूल दौतलपुर का भवन जर्जर होने के कारण 2024 में पंचायत द्वारा तोड़ दिया गया था। इसके बाद यहां नया भवन तैयार नहीं हुआ और किराए के कमरे में स्कूल लग रहा था। स्कूल में आठ बच्चे दर्ज थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में अभिभावकों ने टीसी निकलवा ली हैं और 8 जुलाई को दर्ज संख्या शून्य हो गई है। इसी तरह प्राथमिक स्कूल गोदना में आठ

बच्चे दर्ज थे, लेकिन जर्जर भवन और सुविधाओं के अभाव यहां भी अभिभावकों ने दूसरे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया है, जिससे स्कूल में ताला डल गया है। प्राथमिक स्कूल रुपउ की दर्ज संख्या दो थी और यहां पदस्थ शिक्षक अरविंद दुबे भी कुछ दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे अब यहां भी भी दर्ज संख्या शून्य होने से स्कूल बंद हो गया है। अधिकांश बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में हो गया है। गौरतलब है कि ब्लॉक में दो दर्जन स्कूल बहुत ज्यादा जर्जर हैं और इतने ही स्कूलों की मरम्मत होना है। इसके बाद भी बजट नहीं दिया जा रहा है।

दो स्कूल पहले हो चुके हैं बंद

ब्लॉक के दो प्राथमिक स्कूल उमरिया, रसीलपुर पहले ही दर्ज संख्या शून्य होने के कारण बंद हो चुके हैं। साथ ही एक दर्जन स्कूल बंद होने की कगार पर है, क्योंकि इनमें भी दर्ज संख्या दस से कम है। इसके बाद भी दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही हैं, न ही शिक्षक पदस्थ किए जा रहे हैं।

भेजे जाते हैं प्रस्ताव

नए भवन बनाने और जर्जर भवनों की मरम्मत कराने के लिए वरिष्ठ कार्यालय लगातार प्रस्ताव भेजे जाते हैं। भवन अच्छे न होने पर अभिभावकों ने दूसरे स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिला दिए हैं। कुछ बच्चों के प्रवेश शासकीय स्कूल में हुए हैं। संख्या बढ़ाने लगातार प्रयास हो रहे हैं।

छोरों से मिले घाव पर मरहम लगाती भारत की छोरियां

कसौटी पर अब वनडे के चैंपियन

भले ही पिछले 15 दिनों में टी 20 वर्ल्ड चैंपियन की विदेशी सरजमीं पर क्लीन स्वीप के बाद रोहित,विराट और बुमराह से सजी हुई गिल सेना से क्रिकेट के चाहने वालों को उम्मीद रही होगी।लेकिन इस भिड़ंत के आगाज से ठीक एक दिन पहले भारतीय छोरियों ने बड़ा धमाल कर क्रिकेट के चाहने वालों को मिले हालिया घाव पर कुछ हद तक मरहम लगाने का काम किया है।भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर इतिहास रच दिया है। दरअसल लॉर्ड्स के 142 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका था,जब इस यहां पर महिला टेस्ट मैच खेला गया और भारत की लड़कियों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को शानदार अंदाज में जीतकर यादगार बना दिया।एक ओर जहां अंग्रेजों की जमीन पर मेजबान टीम से भारतीय लड़के पिट रहे थे,उसी सरजमीं पर भारत की लड़कियों ने घरेलू टीम को धूल चटा दी।यह जीत सिर्फ भारत के लिए यादगार नहीं रही,बल्कि यह भिड़ंत भारतीय महिला क्रिकेट के नजरिये से रिकॉर्ड तोड़ मैच भी साबित हुई।तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का पंजा और फिर विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के शतक ने तो दोनों का ही नाम लॉर्ड्स मैदान की उस दीवार पर दर्ज करा दिया जिसमें तमाम दिग्गजों के नाम दर्ज हैं।वहीं स्मृति मंधाना ने भी इस मैच में अपनी शानदार उपलब्धियों से एक बार फिर महिला क्रिकेट को ऊचाइयों पर पहुंचा दिया।भले ही मैच की जीत में इस तिकड़ी का किरदार अहम कहा जा सकता है,लेकिन सच तो यह है कि इनके अलावा स्नेह राना, ऋचा घोष,दीप्ति शर्मा,जेमिमा रोड्रिग्ज और हरमनप्रीत के किरदार को भी इस ऐतिहासिक जीत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।मतलब साफ है कि छोरियों की इस जीत का असल श्रेय पूरी टीम को ही जाता है।वैसे भी टीम गेम में जीत का हीरो/हीरोइन कोई भी बन जाये लेकिन जब

आलोक गोस्वामी
खेल विश्लेषक

भी इतिहास रचा जाता है तो उसकी वजह कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम यूनिट होती है।बस यही वजह है कि वोमेन इन ब्लू ने छोटे फ़ॉर्मेट से हटकर क्रिकेट के उस फ़ॉर्मेट में अपना परचम लहराया जिससे भारतीय लड़के दूर होते जा रहे हैं।दरअसल क्रिकेट के इस फटाफट युग मे भले ही आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण के कारण भारत के लड़कों ने अपनी सोच और नजरिया टेस्ट क्रिकेट के प्रति बदल लिया हो,लेकिन क्रिकेट के असल चाहने व समझने वालों के लिए इसी फ़ॉर्मेट की कद्र अब भी अधिक है।अगर क्रिकेट की बारीकियों की बात करें तो फिर यही वह फ़ॉर्मेट है जिसको कोई भी बड़ा खिलाड़ी कभी नजरअंदाज नहीं कर सका है।मेरे नजरिये में इसी वजह से भारतीय लड़कियों की लॉर्ड्स की जीत के मायने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप के उनके प्रदर्शन से कहीं अधिक है।अब देखना यह दिलचस्प है कि भारतीय लड़कियों ने क्रिकेट खेलप्रेमियों के घाव पर जो मरहम लगयी है उसके बाद वनडे के वर्ल्ड चैंपियन क्या गुल खिलाते हैं।अब अगर हम टी20 में पिटने वाली वर्ल्ड चैंपियन और वनडे की टीम संयोजन पर नजर डालें तो फिर सबसे बड़ा फर्क यही है कि बांये हाथ के भरोसे उतरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताकत अब उसके दांये हाथ मे शिफ्ट हो गयी है।मजेदार बात यह है कि अब टॉप 5 में सभी बल्लेबाज दांये हाथ के मैदान में नजर आयेंगे।सिर्फ ईशान किशन ही बतौर बांये हाथ के बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा है,लेकिन उनको एकादश में शामिल करने के लिए टीम संयोजन में सिर्फ 5 गेंदबाजी विकल्प के फार्मूले पर दांव खेलना होगा।वैसे भी जब से टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर हुए हैं उनका टीम संयोजन का फार्मूला 5 बल्लेबाज, 3 आलराउंडर व 3 गेंदबाज का ही रहा है।भले ही फिर आलराउंडर का प्रयोग कप्तान ने मैदान में किया हो या नहीं।वैसे मेरी यह सोच है कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया 4 शुद्ध गेंदबाजों के फार्मूले से उतार सकती है।वहीं 5 बल्लेबाजों के साथ 2 आलराउंडर इस संयोजन में फिट कर सकती है।मजेदार बात यह भी है कि फ़ॉर्मेट भले ही बदल गया हो लेकिन टीम इंडिया के तीनों आलराउंडर(अक्षर,सुंदर और शिवम) जस के तस हैं। बस फर्क इतना है कि मैदान में इनका इस्तेमाल अब श्रेयष की जगह गिल को करना है।यह पहलू ही सीरीज का सबसे दिलचस्प रहने वाला है।फिर भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रो..को..के सफर ओर उसके सस्पेंस के मद्देनजर आज से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में सबकी टकटकी बुमराह,गिल और राहुल की वापसी पर भी रहेगी।खैर आने वाली इस सीरीज में ऊंठ किस करवट बैठेगा यह तो वक्त ही बतायेगा,लेकिन फिर भी टी20 चैंपियन की करारी हार के बाद उसी जमीन पर लड़कियों ने क्रिकेट के इस खेल में जो कारनामा कर दिखाया उसके बाद सच तो यही है कि कसौटी पर एक बार फिर अब भारत के छोरे ही हैं।

बर्मिंघम में पहले वनडे से नई शुरुआत की तलाश

चार हार का हिसाब चुकाने उतरेगा भारत, अब रोहित-कोहली के बल्ले से पलटवार की उम्मीद

बर्मिंघम, एजेंसी

लगातार छह टी20 मुकाबलों में जीत से दूर रही भारतीय क्रिकेट टीम अब वनडे प्रारूप में नई शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज टीम इंडिया के लिए सिर्फ द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास हासिल करने का सुनहरा अवसर भी है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और फिर इंग्लैंड से 0-4 की करारी टी20 सीरीज हार के बाद भारतीय टीम दबाव में है। ऐसे में एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीदें जुड़ गई हैं। भारतीय समयानुसार पहला मुकाबला दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा।

रोहित-विराट पर टिकी सबसे बड़ी उम्मीद-

करीब दो दशकों से भारतीय बल्लेबाजी की धुरी रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली अब अपने सबसे सफल प्रारूप वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के लिए यह सीरीज अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है। टी20 क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद अब दोनों की पूरी नजर 50 ओवर के प्रारूप में अपनी लय और दबदबा कायम रखने पर होगी। भारतीय टीम को उम्मीद है कि उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा।

इंग्लैंड पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में

हालांकि इंग्लैंड ने जनवरी के बाद कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन हालिया टी20 सीरीज में भारत पर 4-0 की शानदार जीत ने मेजबान टीम का मनोबल काफी ऊंचा कर दिया है। कप्तान हैरी ब्रूक के अलावा जो रूट, जोस बटलर, बेन डकेट और जैकब बेथल जैसी मजबूत बल्लेबाजी इंग्लैंड को बेहद खतरनाक बनाती है। वहीं जोफा आर्चर, जोश टंग और गस एटकिंसन की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

मजबूत बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी की परीक्षा

भारतीय बल्लेबाजी इस बार पहले से अधिक संतुलित नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल शीर्ष क्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर मध्यक्रम को मजबूती देंगे। यदि यह बल्लेबाजी क्रम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करता है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। हालांकि गेंदबाजी विभाग टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। राहत की बात यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से आक्रमण को मजबूती मिलेगी। उनके साथ अर्शदीप सिंह नई गेंद से अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि युवा गुरनूर बरार पर भी सबकी नजर रहेगी। ऑलराउंडर शिवम दुबे को हार्दिक पंड्या और नीतीश कुमार रेड्डी की गैरमौजूदगी में अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव से विकेट निकालने की उम्मीद होगी, जबकि अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

सिर्फ सीरीज नहीं, सम्मान की भी लड़ाई

भारतीय टीम के लिए यह वनडे सीरीज सिर्फ जीत-हार तक सीमित नहीं है। लगातार मिली हार के बाद खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर सवाल उठ रहे हैं और टीम प्रबंधन भी आलोचनाओं के घेरे में है। ऐसे में यदि भारत वनडे में जीत के साथ शुरुआत करता है तो न केवल टी20 की निराशा कुछ हद तक कम होगी, बल्कि आगामी बड़े टूर्नामेंटों के लिए टीम का मनोबल भी मजबूत होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने अनुभव और बल्लेबाजी से टीम इंडिया को फिर जीत की राह पर लौटा पाएंगे।

15 हजार रन से सिर्फ 203 कदम दूर विराट

यह सीरीज कोहली के लिए इतिहास रचने का सुनहरा अवसर भी लेकर आई है। करीब छह महीने बाद भारतीय टीम की वनडे जर्सी में वापसी कर रहे कोहली के सामने कई बड़े रिकॉर्ड हैं। अगर वह इस सीरीज में 203 रन बना लेते हैं तो वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बात पर टिकी होंगी कि क्या किंग कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अपने पसंदीदा मंच पर एक बार फिर बल्ले से इतिहास लिख पाएंगे।

सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका

विराट कोहली ने अब तक भारत के लिए 311 वनडे मुकाबले खेले हैं और 299 पारियों में 58.71 की शानदार औसत से 14,797 रन बनाए हैं। उनके नाम 54 शतक और 77 अर्धशतक दर्ज हैं। 15 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 203 रन की जरूरत है। खास बात यह है कि अगर वह मौजूदा सीरीज में यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो सबसे तेज 15 हजार वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। यह रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 359 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था। विराट के पास यह उपलब्धि महज 302 पारियों के भीतर हासिल करने का मौका है।

सीएसके से अलग हुए स्टीफन फ्लेमिंग

18 साल बाद टूटा आईपीएल का सबसे सफल रिश्ता...

नई दिल्ली, एजेंसी

चेन्नई सुपर किंग्स और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे सफल और लंबे समय तक चली साझेदारियों में से एक का अंत हो गया। यह फैसला फ्लेमिंग और सीएसके प्रबंधन के बीच कई दौर की खुली और ईमानदार बातचीत के बाद आपसी सम्मान और आभार के साथ लिया गया। स्टीफन फ्लेमिंग 2008 में IPL के पहले सीजन में खिलाड़ी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। इसके बाद 2009 में उन्होंने टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली। अगले 17 वर्षों में फ्लेमिंग के नेतृत्व में फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सबसे सम्मानित और सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीमों में शामिल हो गई। फ्लेमिंग के कोच रहते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 आईपीएल खिताब और 2 चैम्पियंस लीग टी20 ट्रॉफियां जीतीं।

टीम मालिक रूपा गुरुनाथ ने क्या कहा?

चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा,स्टीफन फ्लेमिंग लगभग पूरी फेंचाइजी यात्रा के दौरान हमारी कोचिंग इकाई की धड़कन रहे हैं। करीब दो दशकों तक उन्होंने हमारी पहचान, सोच और उत्कृष्टता की संस्कृति को आकार दिया। उन्होंने आगे कहा, सुपर किंग्स परिवार की ओर से हम उनके अटूट समर्पण, जुनून और नेतृत्व के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैदान पर हमारी साझेदारी भले खत्म हो रही हो, लेकिन वह हमेशा इस टीम की विरासत का अभिन्न हिस्सा रहेंगे।

ग्लासगो में फिर होगी नीरज-नदीम की टक्कर अरशद बोले- इस बार जिम्मेदारी ज्यादा है

नई दिल्ली। पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) खिलाड़ी अरशद नदीम ने स्वीकार किया है कि आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरने के कारण उन पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि उन्होंने प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी की है और एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। इस प्रतियोगिता में अरशद नदीम पाकिस्तान दल की अगुवाई करेंगे। साथ ही उनकी भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से एक बार फिर बहुप्रतीक्षित भिड़ंत देखने को मिलेगी। अरशद नदीम ने कहा, इस बार मुझ पर ज्यादा दबाव है क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का डिफेंडिंग चैंपियन हूं। लेकिन मैंने अच्छी तैयारी की है। प्रतियोगिता में वापसी करना अच्छा लग रहा है और मेरा लक्ष्य ग्लासगो में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखना है।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

अब अगले साल आएगी सलमान खान की मातृभूमि?

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अगली फिल्म मातृभूमि की राह ताक रहे फैंस का इंतजार और लंबा हो सकता है। अगर सब ठीक रहता तो इस साल सलमान फैंस को ईद पर अपने हीरो की नई फिल्म देखने को मिल जाती, लेकिन लगातार टलती जा रही इस फिल्म की राह अभी भी आसान नहीं नजर आ रही।

मातृभूमि पहले इस साल अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई थी, लेकिन भारत-चीन सीमा विवाद पर बेस्ड इस फिल्म पर कुछ आपत्तियों के बाद पहले कंटेंट में कुछ बदलावों के लिए फिल्म को टाला गया। फिर खबर आई कि मातृभूमि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आ सकती है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि सलमान की फिल्म अगले साल तक भी जा सकती है।

लगातार तारीख टालने के बाद अब रिलीज डेट का क्राइसिस!

बॉलीवुड हंगामा से जुड़े एक ट्रेड सूत्र ने बताया है कि मातृभूमि के मेकर्स इस साल ही फिल्म रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब ये भी एक संभावना है कि फिल्म 2027 तक टल सकती है। सूत्र ने बताया, मामला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। अगर जल्द सुलझ भी जाता है, तो भी अच्छी रिलीज डेट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े स्लॉट पहले ही बुक हो चुके हैं। इंडस्ट्री में अक्सर स्टार्स और फिल्ममेकर्स किसी दूसरी फिल्म की अनाउंस हो चुकी रिलीज डेट पर अपनी फिल्म भी ले आते हैं, लेकिन सलमान खान इस मामले में अलग हैं। वो बहुत निष्पक्ष हैं और बिना वजह किसी दूसरी फिल्म से क्लैश नहीं चाहते। अगर कभी क्लैश का फैसला भी लेते हैं, तो पहले सामने वाले को इसकी जानकारी देते हैं।

दशहरे का वीकेंड हो सकता है अच्छा विकल्प

एक इंडस्ट्री इनसाइडर के मुताबिक, दशहरे का वीकेंड मातृभूमि के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. उन्होंने कहा, %इस साल दशहरा 20 अक्टूबर, मंगलवार को है. आमतौर पर दशहरे से एक दिन पहले भी छुट्टी जैसा माहौल रहता है और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बढ़ जाते हैं. ऐसे में मातृभूमि को लगभग पांच दिन का लंबा वीकेंड मिल सकता है. वहीं %रामायण% के प्रीपोन होकर, 30 अक्टूबर को रिलीज होने की उम्मीद है. उसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते तक कोई बड़ी फिल्म नहीं है, जिसका

मेट्रो बाजार

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में जनवरी-जून अवधि में आया 3.2 अरब डॉलर का निजी इक्विटी निवेश

नई दिल्ली। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में जनवरी-जून अवधि यानी 2026 की पहली छमाही में 3.2 अरब डॉलर का निजी इक्विटी निवेश आया है। इसमें सालाना आधार पर 33 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की दूसरी तिमाही में निवेश का प्रवाह 2 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

प्राइवेट इक्विटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट रूट से किए गए इक्विटी डील, एआईएफ और एनसीडी जारी करने के जरिए स्ट्रक्चर्ड डेट डील शामिल हैं, लेकिन इसमें फंड जुटाने में क्यूआईपी, पब्लिक मार्केट डील और प्लेटफॉर्म बनाने के जरिए किए गए साधारण डेट डील शामिल नहीं हैं। 2026 की दूसरी तिमाही में हुए कुल निवेश में डेटा सेंटर्स का हिस्सा 38 प्रतिशत रहा, जिससे ऑफिस-आधारित निवेश के ट्रेंड में बदलाव दिखा। इसके बाद ऑफिस सेगमेंट का 30 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि रेजिडेंशियल सेगमेंट 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कुल मिलाकर, 2026 की पहली छमाही में ऑफिस सेगमेंट सबसे आगे रहा, जिसमें इक्विटी निवेश का 34 प्रतिशत हिस्सा शामिल था। निवेशकों ने हॉस्पिटैलिटी (8 प्रतिशत) और स्टूडेंट हाउसिंग या को-लिविंग (3 प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया।

सेबी ने कर्मचारियों के लिए सख्त किए नियम बाजार में निवेश-नौकरी बदलने पर बढ़ी निगरानी

नई दिल्ली। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आचार संहिता को और सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत हितों के टकराव को रोकने, निवेश पर निगरानी बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए गए हैं। सेबी ने एसईबीआई (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2026 को अधिसूचित करते हुए कर्मचारियों के निवेश, खुलासे और नौकरी से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं।

नए नियमों के तहत सेबी ने परिवार और आश्रित की परिभाषा का विस्तार किया है। अब इसमें गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे, जो किसी कर्मचारी पर काफी हद तक आर्थिक रूप से निर्भर हैं। इस बदलाव के बाद निवेश, खुलासे और अन्य सेवा संबंधी नियमों का दायरा भी पहले से व्यापक हो जाएगा।

संशोधित नियमों के अनुसार, सेबी से इस्तीफा देने या रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर दो साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू होगा। इस अवधि के दौरान पूर्व कर्मचारी किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से सेबी के समक्ष किसी मामले में पैरवी नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध जांच, सुनवाई, सेटलमेंट और विभिन्न मंजूरियों से जुड़े मामलों पर लागू होगा। यदि कोई सेबी कर्मचारी किसी अन्य संस्थान या कंपनी में नौकरी के लिए बातचीत शुरू करता है, तो उसे एक महीने के भीतर इसकी जानकारी सेबी को देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य संभावित हितों के टकराव को रोकना और नियामकीय पारदर्शिता को मजबूत करना है। सेबी ने अपने कर्मचारियों के निवेश नियम भी काफी सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य

गोविंदा 50 अफेयर भी करें तब भी...वाले बयान पर बोलीं सुनीता आहूजा-

मुझे किसी बात का पछतावा नहीं

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी बीच सुनीता आहूजा एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में रियलिटी शो लॉक अप- सच या सजा में उन्होंने अपने पति गोविंदा को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। सुनीता ने कहा था कि अगर गोविंदा के 50 अफेयर भी हों, तब भी वह उन्हें नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वह उनके पति हैं।

शो के दौरान सुनीता आहूजा ने अपनी बात खुलकर रखी। शिल्पा शिंदे और राम कपूर से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी जगह खुद को रखकर देखो, तब समझोगे कि मैं क्या महसूस करती हूं। वह मेरे पति हैं। मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरे पति के 50 अफेयर भी हों, तो इससे किसी और का क्या जाता है? वह मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूं। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने उनके रिश्ते पर भरोसे की तारीफ की, तो कुछ ने उनके बयान पर सवाल भी उठाए।अब शो से बाहर आने के बाद आईएएनएस ने जब सुनीता आहूजा से पूछा कि क्या उन्हें अपने इस बयान पर कोई पछतावा है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो भी कहा, वह दिल से कहा और आज भी उसी बात पर कायम हूं।

सुनीता ने आगे अपने और गोविंदा के रिश्ते के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, अगर आपका प्यार सच्चा है, जैसा मेरा और गोविंदा का है, तो आपको अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी शादी को 40 साल हो चुके हैं। सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है।

धरती का उल्टा पेड़, हजारों साल तक जीवित रहने वाला बाओबाब

अफ्रीका के विशाल मैदानों में खड़ा बाओबाब वृक्ष प्रकृति के सबसे अनोखे और रहस्यमयी पेड़ों में गिना जाता है। अपनी विशाल तने और ऊपर की ओर फैली जड़ों जैसी दिखाई देने वाली शाखाओं के कारण इसे 'उल्टा पेड़' भी कहा जाता है। यह पेड़ हजारों लीटर पानी अपने तने में संग्रहित करने की क्षमता रखता है, जिससे यह लंबे सूखे और कठिन मौसम में भी जीवित रहता है। बाओबाब केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि कई जीव-जंतुओं और पक्षियों के लिए आश्रय स्थल भी है। अफ्रीका के कई क्षेत्रों में इसे जीवन, धैर्य और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अपनी अद्भुत बनावट और लंबी आयु के कारण यह दुनिया भर के पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है।

यूएनएससी सीट के लिए भारत का मिशन शुरू, जयशंकर बोले-

आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और समुद्री सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता

नई दिल्ली। एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 2028-29 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य बनने की दावेदारी के तहत भारत ने अपना स्पष्ट एजेंडा दुनिया के सामने रखा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आज को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यदि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना जाता है, तो वह आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती तकनीकों के जिम्मेदार एवं मानव-केंद्रित उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाएगा।

जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद आज भी दुनिया के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब तक दुनिया आतंकवाद के केवल लक्षणों से लड़ती रही है, जबकि स्थायी समाधान तभी संभव है जब आतंकियों की आर्थिक और वित्तीय ताकत को खत्म किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्रतिबद्धता आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रभावी रोक लगाने की है। साथ ही हम आतंकवादी संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए वस्तुनिष्ठ और ठोस साक्ष्यों पर आधारित प्रस्तावों को बढ़ावा देंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) के जरिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में समुद्री व्यापार का सुरक्षित और निर्बाध संचालन पूरी दुनिया के हित में है। हाल की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना इस दिशा में पहली आवश्यकता है।

डिजिटल डिवाइड और एआई के दुरुपयोग पर भारत की सोच

जयशंकर ने कहा कि भारत ने दुनिया में डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में लगातार योगदान दिया है और एआई के क्षेत्र में भी उसकी सोच समान रूप से समावेशी है। इसी उद्देश्य से हाल ही में भारत में आयोजित AI Impact Summit की थीम 'AI for All' रखी गई थी। उन्होंने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि एआई का लाभ सभी देशों और समाजों तक पहुंचे। साथ ही भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग और उससे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को पैदा होने वाले खतरों का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला करेगा।

एआई को लेकर भारत का दृष्टिकोण

उभरती तकनीकों का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी लेकर आई है। इसलिए इसके उपयोग के लिए मानव-केंद्रित और जिम्मेदार शासन व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत ने एआई के लिए MANAV फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। इसका अर्थ है Moral and Ethical Systems (नैतिक एवं आचार आधारित व्यवस्था), Accountable Governance (जवाबदेह शासन), National Sovereignty (राष्ट्रीय संप्रभुता), Accessible and Inclusive (सभी के लिए सुलभ एवं समावेशी व्यवस्था) तथा Valid and Legitimate Systems (वैध और विश्वसनीय प्रणाली)। वहीं, जयशंकर ने कहा कि भारत लंबे समय से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। खोज एवं बचाव अभियान, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना भारत की प्रमुख पहलों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत का इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगी नेटवर्क का संचालन कर रहा है। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्री सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उचित महत्व मिले।

मध्यप्रदेश में पैडल पर सियासत

जीतू की इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा शुरू, युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

इंदौर। दोपहर मेट्रो

एमपी कांग्रेस द्वारा आज से इंदौर से भोपाल तक एक विशेष साइक्लोथॉन (साइकिल यात्रा) शुरू की है। यह यात्रा नीट यूजी परीक्षा में धांधली, सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं के विरोध में निकाली जा रही है। राहुल गांधी के अभियान 'छात्रों की गूंज' के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद कर रहे हैं। वे स्वयं साइकिल चलाते हुए दो दिनों में इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे। यह पूरी साइक्लोथॉन दो दिवसीय होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करना है। यह साइकिल यात्रा आज 14 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के पास स्थित आरएनटी (रवीन्द्र नाथ टैगोर) मार्ग से प्रारंभ हुई। उल्लेखनीय है कि इंदौर में यह क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कांग्रेस ने इस स्थान का चयन विशेष रूप से किया है ताकि यहां से छात्रों की समस्याओं और सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर एक बड़ा और प्रभावी संदेश दिया जा सके।

कर्नाटक: केस जीतने के लिए जज की सीट पर छिड़के सरसों के दाने, काला जादू के आरोप में महिला गिरफ्तार

चिक्काबल्लापुर. एजेंसी। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में सीनियर सिविल जज और जेएमएफसी कोर्ट के जज की कुर्सी पर कथित तौर पर काला जादू करने के आरोप में 65 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, मंजुला नाम की आरोपी महिला कथित तौर पर कोर्ट परिसर में घुसी और जज की कुर्सी पर मंत्र-फूंके हुए सफेद सरसों के दाने छिड़ककर काला जादू किया। पुलिस ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब दो दिन पहले रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज में महिला को कोर्टरूम के अंदर यह हरकत करते हुए देखा गया। अधिकारी ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज में महिला को दो दिन पहले जज की कुर्सी पर कथित तौर पर जादुई सफेद सरसों के दाने छिड़कते हुए देखा गया। कोर्ट की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नेत्रा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और इसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला के खिलाफ कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

न्यूज विंडो

रेलवे ने मप्र, यूपी और गुजरात को जोड़ने वाली 11 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए

रतलाम। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष किराये पर संचालित 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का पुन: विस्तार किया है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि विस्तारित अवधि में ये ट्रेनें अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी।

विस्तारित ट्रेनों में दादर-प्रयागराज स्पेशल, दादर-सूबेदारगंज स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज स्पेशल, बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, वलसाड-सूबेदारगंज स्पेशल, उधना-आगरा कैंट स्पेशल, उधना-प्रयागराज स्पेशल, असारवा-कानपुर सेंट्रल स्पेशल और असारवा-आगरा कैंट स्पेशल सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं।

तिरुवल्लूर की फैक्ट्री में लगी आग एक मजदूर की मौत, सात घायल

तिरुवल्लूर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में आज एक प्राइवेट मेटल स्मेल्टिंग फैक्ट्री में एक बड़ा बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना पार्थ पालयम गांव के पास गुमिडिपुंडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हुई। तिरुवल्लूर पुलिस के अनुसार, मरने वाले की पहचान बिहार के रहने वाले रवि रंजन के तौर पर हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले चार घायल कर्मचारियों भूषण कुमार, ओम कुमार, रंजीत कुमार और सिंबर सिंह को इलाज के लिए गुमिडिपुंडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, हिंदू पक्ष की ओर से पैरवी करेंगे विष्णु

नई दिल्ली/धार, एजेंसी

धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। तीनों में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। ये सभी हाईकोर्ट में दायर मूल याचिका में याचिकाकर्ता की भूमिका में थे।

फैसले को तीन पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है

भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष के 365 दिन वहां पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को तीन पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट भोजशाला से जुड़ी तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। भोजशाला को इंदौर हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिर माना है। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले के बाद आने वाले पहले शुक्रवार से एक दिन पहले दायर की गई थी। पहले शहर काजी, फिर कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी और उसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से जिब्रान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले गुजरात ATS ने पकड़े पांच संदिग्ध

अहमदाबाद। एजेंसी

अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा निकलने में अब केवल 2 दिन का समय शेष है। इस बड़े उत्सव से ठीक पहले गुजरात एटीएस ने सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस की टीम ने सिद्धपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, 16 जुलाई को अहमदाबाद, भावनगर, वडोदरा, पाटन और राजकोट सहित कई शहरों में रथयात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने के इरादे से कुछ संगठनों के सक्रिय होने की खुफिया जानकारी मिली थी। जांच के दौरान आतंकी संगठनों के तार सिद्धपुर तालुका से जुड़े होने के सबूत मिले, जिसके बाद एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और 5 संदिग्धों को पकड़ा। इन संदिग्धों का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद या किसी अन्य संगठन से है या नहीं, इस दिशा में विस्तृत जांच की जा रही है। इसके अलावा, बनासकांठा से भी 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। रथयात्रा जैसे संवेदनशील त्यौहारों को देखते हुए गुजरात पुलिस और एटीएस अलर्ट मोड पर हैं।

मेट्रो एंकर **पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता**

इज्जत बचाने के लिए माता-पिता दर्ज कराते हैं एफआईआर

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किशोरों के आपसी सहमति से बने रिश्तों में पॉक्सो एक्ट के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब टीनेज लड़कियां अपने पार्टनर्स के साथ परिवार वालों के बिना अनुमति के शादी करने लेतीं हैं, तो माता-पिता अक्सर अपनी तथाकथित 'इज्जत' बचाने के लिए आपराधिक मामले दर्ज करा देते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में सवाल किया कि कोई राज्य किसी लड़के और लड़की को भागने से कैसे रोक सकता है? पॉक्सो एक्ट बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए है। 15 से 18 साल की उम्र एक संवेदनशील उम्र होती है, क्या ऐसे मामलों को सच में पॉक्सो के तहत लाना सही है? बता दें कि यह सुनवाई किशोरों के 'निजता के अधिकार' को लेकर कोर्ट द्वारा खुद शुरू किए गए एक मामले पर हो रही थी। दरअसल, कुछ समय पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि किशोर लड़कियों को रिश्तों में पड़ने के बजाय अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कोर्ट को बताया कि जिस मामले की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने वह टिप्पणी की थी, उसमें एक नाबालिग लड़की 25 साल के व्यक्ति के साथ भागकर शादी कर ली थी। वह लड़की अब उस व्यक्ति के साथ पत्नी की तरह खुशी-खुशी रह रही है और उनका एक बच्चा भी है। वहीं सोशल वर्कर्स की एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हो रहा है, क्योंकि 17-18 साल के लड़कों को जेल भेज दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

मामले में कोर्ट ने आगे कहा कि 16 से 18 साल के किशोर आपस में रिश्ता बनाकर चले जाते हैं। माता-पिता कानूनी कार्रवाई का सहारा लेते हैं, लेकिन आखिर में हमें उन्हें बरी ही करना पड़ता है। बता दें कि साल 2012 में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। मामले में इस बात को आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यह बदलाव 2012 के बाद आया है, यह पहले भी बाल विवाह की तरह होता था। लेकिन उम्र 18 साल तय होने से अब यह गैरकानूनी हो जाता है। मामले में अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सरकार और कोर्ट के निर्देश व्यावहारिक होने चाहिए ताकि किसी का भविष्य बर्बाद न हो।

सरकार का सुझाव- स्कूल से ही दी जाए जागरूकता

मामले में केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के वकील के अनुसार कक्षा 6 से ही बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से पॉक्सो एक्ट और किशोर शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। हालांकि जब वकील ने सुझाव दिया कि पॉक्सो मामलों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार का एक डैशबोर्ड होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाई कोर्ट के पास पहले से ही बाल अधिकारों के लिए एक कमेटी है और राज्य सरकारें इसकी निगरानी कर सकती हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक राजेश सिरोठिया द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) फोन : 0755-7963564